आज का विचार

ये दबदबा, ये हुकूमन, ये दौलतें... सब किराएदार हैं, समय-समय पर घर बदलते रहते हैं।

दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । शनिवार, 28 मार्च, 2026 वर्ष 24, अंक 75, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 28 हजार 582 करोड़ की लागत से 1 हजार 719 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण: सैनी

मुख्यमंत्री ने 'सड़क सुरक्षा समाधान विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय आई.आर.सी सेमिनार का किया उद्घाटन

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। ब्लैक स्पॉट की पहचान और सुधार, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का आधुनिकीकरण, जागरूकता अभियान और नई तकनीकों का उपयोग के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को चंडीगढ़ में भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी) एवं लोक निर्माण विभाग हरियाणा द्वारा 'सड़क सुरक्षा समाधान' विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन करने के पश्चात अपना संबोधन दे रहे थे। कार्यक्रम में हरियाणा के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरूआत मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्जवलित कर की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान रामनवमी और नवरात्रों की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी।

सेमिनार में भारतीय सड़क कांग्रेस के प्रतिष्ठित सदस्यगण के अलावा 350 से अधिक विशेषज्ञ, अभियंता. शोधकर्ता, नीति-निमार्ता तथा शिक्षाविद शिरकत कर रहे हैं। दो दिनों तक चलने वाली संगोष्ठी में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार मंथन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 'सड़क सुरक्षा समाधान विषय पर आयोजित संगोष्ठी देश के भविष्य का रोडमैप तैयार करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यहां विचार, तकनीक, अनुभव और संकल्प मिलकर भारत को सुरक्षित, सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सड़क केवल एक भौतिक संरचना नहीं होती, यह विकास की जीवन रेखा होती है। यह गांव को शहर से जोड़ती है, किसान को बाजार से जोड़ती है, युवा को अवसरों से जोड़ती है और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। लेकिन, यह भी एक कटु सत्य है कि जहां सड़क विकास का माध्यम है, वहीं सड़क दुर्घटनाएं हमारे समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं।

सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में हर वर्ष काफी संख्या में लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। इन दुर्घटनाओं के पीछे टूटे हुए परिवार, अधूरे सपने और समाज की अपूरणीय क्षति छिपी रहती है। इसलिए सड़क सुरक्षा केवल एक तकनीकी विषय न होकर सामाजिक, मानवीय और नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, यातायात नियमों के प्रति जन-जागरूकता। नियम कितने भी अच्छे क्यों न हों, यदि उनका पालन नहीं किया जाएगा, तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, गति सीमा का पालन करना, ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन जीवन को बचाती हैं। उन्होंने कहा कि हमें स्कूलों, कॉलेजों और समाज के हर वर्ग तक सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। हमें इसके प्रति और गम्भीर होना होगा। क्योंकि, सड़क सुरक्षा ही जीवन सुरक्षा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो 'विकसित भारत 2047' का संकल्प लिया है। उसे पूरा करने में आधुनिक, सुरक्षित और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका यह प्रयास, उनका यह विजन, विकसित भारत-विकसित हरियाणा के निर्माण की दिशा में एक और मील का पत्थर है। उनकी दूरदर्शी सोच, तेज निर्णय क्षमता और विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांति ला दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज, देश भर में, हम कहीं भी जाएं, वहां कोई न कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का कार्य प्रगति पर है। चाहे वह मेट्रो हो या फ्रेट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, बड़े पुल हो या बंदरगाह का विकास हो। देश के हर हिस्से में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास का कार्य हो रहा है। साथ ही, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'रोड सेफ्टी' को भी उतनी ही प्राथमिकता दी है।

रसोई गैस उत्पादन में 40 फीसदी वृद्धि, कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति 70 फीसदी तक बहाल: केंद्र

पेट्रोल-डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर घटी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

पश्चिम एशिया युद्ध के कारण वैश्विक रुकावटों के बावजूद भारत ने कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है। साथ ही घरेलू रसोई गैस के उत्पादन में लगभग 40 फीसदी की वृद्धि हुई है। घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है, जबकि कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति को धीरे-धीरे 70 फीसदी तक बहाल कर दिया गया है, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के कारण ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने शुक्रवार को यहां आयोजित प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी दी। शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती की है। इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय स्वयं वहन किया है, जिससे पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क 10-10 रुपये प्रति

लीटर कम हो गया है। अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतें या तो कम हुई हैं या स्थिर बनी रही हैं। यहाँ तक कि अप्रैल 2025 में जब उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया था तब भी इसका अतिरिक्त बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया।

सुजाता शर्मा ने कहा कि पीएनजी के विस्तार कार्य में तेजी लाई गई है, जिसके तहत प्रतिदिन 10,000 से अधिक नए कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। साथ ही जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है, जिसके तहत लगभग 3 हजार छापेमारी की गई है, सैकड़ों एफआईआर दर्ज की गई हैं और गैस वितरकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर अनावश्यक खरीदारी न करें।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एक युद्ध जैसी स्थिति में हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध की वजह से कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी की हमारी आपूर्ति पर असर पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और अन्य उत्पादों की कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। हालांकि, भारत सरकार ने इस स्थिति को बहुत प्रभावी ढंग से संभालने के लिए कई स्तरों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं...।

सुजाता शर्मा ने कहा, इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप 14 मार्च से लेकर 26 मार्च तक कमर्शियल उपभोक्ताओं को लगभग 30,000 टन कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति की गई है। जब भारत सरकार ने ये निर्णय लिए तो उसने यह सुनिश्चित किया कि रेस्तरां, ढाबों, होटलों, औद्योगिक कैंटीनों, प्रवासियों और श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाए...। वहीं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव सेंथिल राजन ने कहा कि हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और फेक न्यूज से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि इससे पहले एलपीजी की कमी के बारे में गलत जानकारी फैलने से लोग घबराकर बुकिंग करने लगे थे, लेकिन उस स्थिति को काबू में कर लिया गया था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और नागरिकों को पेट्रोल पंपों पर भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। राजन ने कहा कि गलत जानकारी फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं और लोगों से आग्रह है कि वे ऐसी बातों पर विश्वास न करें।

पश्चिम एशिया संकट के बीच बीच केंद्र ने दी जनता को राहत

केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच बीच आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर घटा दिया है। सरकार ने पेट्रोल पर इसको 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर अब 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीजल पर इसको 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य (0) कर दिया है। नई दरें शुक्रवार से लागू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय की आज जारी अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है जबकि डीजल पर यह शुल्क पहले के 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, सरकार के इस कदम से पेट्रोल- डीजल की कीमतें कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के लिए एक नया लेवी ढांचा पेश किया है।

बजट 2026-27 पर संसद की मुहर

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

संसद ने शुक्रवार को वित्त विधेयक 2026-27 को अपनी मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने ध्वनिमत से इसे लोकसभा को वापस भेज दिया, जिससे एक अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट की प्रक्रिया पूरी हो गई। लोकसभा ने 25 मार्च को 32 संशोधनों के साथ इस विधेयक को पारित किया था। इसके साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही 30 मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी

राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद वित्त विधेयक को लोकसभा को वापस भेज दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दिए। इसके साथ ही संसद से केंद्रीय बजट 2026-27 को मंजूरी मिल गई। इससे पहले सीतारमण ने राज्यसभा में विनियोग (2) विधेयक, 2026 और वित्त विधेयक, 2026 पर चर्चा का संयुक्त जवाब दिया। इसके बाद सदन ने केंद्रीय बजट 2026-27 को अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में दोनों विधेयक पर चर्चा का संयुक्त जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि एक वर्ष (2025) में राजस्व विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 में सुधार किए, और एक नई आयकर प्रणाली शुरू की है, जो अधिक सरल और जिसका पालन करना आसान है। उन्होंने पश्चिम एशिया संकट पर कहा कि सरकार सक्रिय है और बदलती स्थिति पर नजर रख रही है।

सीतारमण ने कहा कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण कई देशों में स्थिति खराब है। भारत में हम इससे अच्छी तरह से निपट रहे हैं। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि देश में लॉकडाउन की कोई गुंजाइश नहीं है, नेताओं को अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए। हम सतर्क रहेंगे। राजकोष का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करेंगे। पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के बावजूद डीजल और पेट्रोल की कीमतें अपरिवर्तित हैं। वित्त मंत्री ने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि पेंशन प्रशासन प्रणाली (स्पर्श) यह सुनिश्चित करता है कि निधि ठीक समय पर सीधे खातों में ट्रांसफर हो जाएं। पैसा तभी जारी किया जाता है जब राज्य सरकारें भी अपना हिस्सा देती हैं, जिससे यह पक्का होता है कि दोनों ही बिना किसी देरी के जमीनी स्तर तक पहुंचें। एक बार उपयोग प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद, अगली किस्त जारी कर दी जाती है और यह चक्र चलता रहता है।

30 से अधिक वस्तुएं जीएसटी से मुक्त

सीतारमण ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट संसाधनों का इंतजार नहीं करता और फंड्स को बेवजह रोककर नहीं रखा जाता। वित्त मंत्री ने डीएमके सांसद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल पर पार्टी की मीटिंग में डीएमके मौजूद नहीं थी। वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि 30 से ज्यादा चीजें जीएसटी से मुक्त हैं, अगर जरूरत हुई तो मैं उनकी सूची शेयर कर सकती हूं। इनका इस्तेमाल हर कोई करता है, खासकर गरीब और आम नागरिक। सीतारणम ने कहा कि सितंबर में हमने जीएसटी से मुक्त कैटेगरी में और भी कई चीजें शामिल कीं है। उन्होंने बताया कि दालें और अनाज जीएसटी से मुक्त हैं। ताजे फल और सब्जियां जीएसटी से से मुक्त हैं। आटा, मैदा और बेसन जीएसटी से मुक्त हैं। ताजी ब्रेड, गुड़ वगैरह ये सभी जीएसटी से मुक्त हैं। इससे पहले वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में विचार और वापसी के लिए वित्त विधेयक, 2026 और विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2026 दोनों विधेयक को एकसाथ पेश किया था। लोकसभा ने बुधवार को 32 सरकारी संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2026 पारित कर दिया था। राज्यसभा से वित्त विधेयक 2026 के पारित होने के साथ ही लोकसभा ने बजटीय अनुमोदन प्रक्रिया में अपनी भूमिका पूरी कर ली है।

जोजिला दर्रे में हिमस्खलन से यात्री वाहन दबा, 7 लोगों की मौत

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

लद्दाख क्षेत्र के जोजिला दर्रे पर शुक्रवार को हुए भीषण हिमस्खलन में बड़ा हादसा हो गया। एक यात्री वाहन हिमस्खलन की चपेट में आकर बर्फ में दब गया, जिससे कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, वाहन अचानक आए भारी हिमस्खलन के कारण पूरी तरह बर्फ के नीचे दब गया। घटना के तुरंत बाद राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। मलबे से शवों को

निकालने और घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य जारी रहा। घायलों को नजदीकी चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया गया है।

लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें जोजिला में हुए हिमस्खलन की जानकारी मिलते ही उन्होंने कारगिल के उपायुक्त (डीसी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि आपदा राहत बलों और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) सहित सभी संबंधित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि बचाव कार्य तेजी से पूरा किया जा सके। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि वे स्वयं स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, कठिन मौसम और बर्फीले हालात के कारण बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, लेकिन राहत और निकासी कार्य लगातार जारी है।

शुष्क क्षेत्र अब कृषि उत्पादन के नए केंद्र बन रहे हैं: शिवराज चौहान

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुष्क खेती, जलवायु अनुकूल किस्मों से लेकर सिंचित क्षेत्रों तक किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। शुष्क क्षेत्र अब कृषि उत्पादन के नए केंद्र बन रहे हैं। जलवायु अनुकूल फसल किसानों की आय बढ़ा रही है। राज्यसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल में शिवराज सिंह चौहान शुष्क खेती, जलवायु-अनुकूल किस्मों, श्री अन्न (मिलेट्स), पंजाब-महाराष्ट्र जैसे कृषि-प्रधान राज्यों की चुनौतियों और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर पूछे गए प्रश्नों और पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। महाराष्ट्र के शुष्क जिलों को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कभी भारत को खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर रहना होता था। देश पीएल-480 योजना से मिलने वाले गेहूं पर निर्भर था। अब स्थिति पूरी बदल चुकी है, देश के अन्न भंडार भरे हैं और चावल उत्पादन में भारत चीन को पछाड़ कर दुनिया में नंबर एक स्थान पर पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने मराठवाड़ा के 23 शुष्क जिलों के लिए

808 जलवायु के अनुसार संवेदनशील किस्मों का बड़ा अभियान चलाया है।

शिवराज सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र के 23 जिले शुष्क भूमि वाले हैं और 13 जिले वर्षा-आश्रित हैं, जिनमें छत्रपति संभाजी नगर, जलना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, परभणी, हिंगोली जैसे मराठवाड़ा के जिले शामिल हैं। कृषि मंत्रालय जलवायु अनुकूल फसलों और खेती के लिए इन इलाकों के लिए विशेष परियोजनाएं तैयार की हैं, इन्हें कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से किसानों तक निरंतर पहुंचाया जा रहा है। इसमें महाराष्ट्र के लिए 808 उच्च उपज देने वाली जलवायु- प्रतिरोधक फसल किस्मों में 332 अनाज, 122 तिलहन, 61 दलहनी, 198 रेशेदार फसलें, 19 गन्ना और 8 अन्य संभावित फसलों की किस्में हैं जो विशेष रूप से शुष्क और वर्षा-निर्भर खेती के लिए अनुकूल हैं।

उत्तर प्रदेश में सज्जनों का संरक्षण, दुर्जनों के लिए जीरो टॉलरेंस : सीएम योगी आदित्यनाथ

एजेंसी (हि.स.)
गोरखपुर,

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा के बेहतर माहौल के साथ सरकार रामराज्य की अवधारणा को साकार कर रही है। यहां हर सज्जन शक्ति का संरक्षण है, लेकिन दुर्जन के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए संवेदना है, लेकिन भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। यूपी में विरासत का सम्मान है और विकास की गारंटी भी।

गोरखनाथ मंदिर में शुक्रवार को कन्या पूजन के बाद प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्रि की नवमी तिथि एवं श्रीरामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रामराज्य की अवधारणा से बिना भेदभाव शासन की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में 06 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर उन्हें सम्मानजनक जीवनयापन करने के अवसर प्रदान किए गए हैं। हर क्षेत्र में विकास के साथ प्रदेश में 02 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय, 65 लाख परिवारों को पीएम-सीएम आवास योजना का लाभ मिला है। लगभग 10 करोड़ लोगों को पीएम-सीएम जन आरोग्य योजना में 05 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया गया है। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चैत्र शुक्ल नवमी, वासंतिक नवरात्रि की सिद्धि प्रदान करने वाली, सुख-समृद्धि और सर्वत्र खुशहाली प्रदान करने वाली पावन तिथि है। वासंतिक नवरात्रि की नवमी तिथि पर मयार्दा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का पावन जन्मोत्सव भी रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। प्रभु

श्रीराम भारत के सनातन धर्म की परंपरा में भारतीय जीवन पद्धति के एक अत्यंत पवित्र आदर्श के रूप में हर सनातन धर्मावलंबी के लिए सदैव से प्रेरणा रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु श्रीराम का आदर्श जीवन चरित्र सबको प्रेरणा प्रदान करता है।

प्रभु श्रीराम से प्रेरणा लेने वाले हर भारतीय को आज सुखद अनुभूति

सीएम योगी ने कहा कि प्रभु श्रीराम के पावन जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने वाला हर भारतीय आज सुखद अनुभूति कर रहा है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से रामलला की भव्य-दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। राम दरबार में प्रभु श्रीराम, माता जानकी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी के साथ पवनसुत हनुमान जी विराजमान हो चुके हैं। 25 नवंबर 2025 को पीएम मोदी ने भव्य राम मंदिर में भारत के सनातन धर्म के प्रतीक केसरिया ध्वज के आरोहण का कार्य भी संपन्न किया था।

नवरात्रि मातृशक्ति के प्रति सनातन धर्म की श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक

सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म के सभी व्रत और पर्व हम सबको जीवन में संकल्पित होने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। वासंतिक हो या शारदीय नवरात्रि, यह मातृशक्ति के प्रति सनातन धर्म की श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। इसी को ध्यान में रखकर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार मिशन शक्ति के माध्यम से नारी शक्ति की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए कार्यक्रम संचालित कर रही है। मातृ वंदना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों के साथ ही यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20 फीसदी महिला आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में वर्तमान में 44,000 से अधिक महिला पुलिस अधिकारी और कार्मिक सफलतापूर्वक इस अभियान को आगे बढ़ाकर महिला सुरक्षा और स्वावलंबन में योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी नवरात्रि की प्रतिपदा पर 19 मार्च को राष्ट्रपति अयोध्या आईं और उन्होंने श्री रामजन्मभूमि मंदिर के ऊपरी तल में श्रीराम यंत्र की स्थापना की। अयोध्या में हुए इन कार्यों को देश और दुनिया के हर सनातन धर्मावलंबी ने अपनी आंखों से देखा है और आनंद की अनुभूति भी की है। हर सनातनी अपने जन्म और जीवन को धन्य-धन्य महसूस करता है। कई-कई पीढ़ियां जो कार्य नहीं देख पाईं, वह उन्होंने अपने जीवन में अपनी आंखों से देखा है।

स्मार्ट मीटर से बढ़ा बिल आए तो एक साल के रिकॉर्ड से होगी जांच: मुख्यमंत्री सुक्खू

कहा, राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का काम केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत किया जा रहा

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट बिजली मीटरों को लेकर बढ़ते बिलों की शिकायतों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अगर किसी उपभोक्ता का बिल स्मार्ट मीटर लगने के बाद ज्यादा आता है, तो उसकी जांच पिछले एक साल के बिजली बिलों के आधार पर की जाएगी और जहां कमी मिलेगी, उसे ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में उपभोक्ता संबंधित एक्स-ईएन (एक्सईएन) से शिकायत कर सकते हैं, जिनको जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने यह बात शुक्रवार को विधानसभा में विधायक राम कुमार के अनुपूरक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का काम केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत किया जा रहा है और इनके लिए जरूरी मानक पहले से तय हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि राज्य सरकार स्मार्ट मीटर लगाने का काम नहीं करती है, तो केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि में कटौती हो सकती है। विधानसभा में विधायक आशीष बुटेल के मूल प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि आरडीएसएस-एक और आरडीएसएस-दो योजना के तहत पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर, बिजली लाइन और सब-स्टेशन जैसे कार्यों के लिए 3224.07 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के दो मुख्य घटक हैं लॉस रिडक्शन वर्क्स और स्मार्ट मीटरिंग वर्क्स। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉस रिडक्शन से जुड़े कार्य मैसर्ज आरवीएनएल को सौंपे गए हैं, जबकि स्मार्ट मीटर लगाने का काम मैसर्ज अपरावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। उन्होंने बताया कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 42 हजार 934 बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से अब तक 1179 उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और बाकी उपभोक्ताओं के मीटर बदलने का काम अभी जारी है।

निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाएगी सुक्खू सरकार, नियमों में करेगी संशोधन

शिमला। हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की शिकायतों के बीच राज्य सरकार नियमों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा में विधायक राम कुमार के प्रश्न के जवाब में दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा सहित कई राज्यों में निजी स्कूलों की फीस को लेकर नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी इन्हीं राज्यों की तर्ज पर नियमों में संशोधन करेगी, जिससे निजी स्कूलों द्वारा ज्यादा फीस वसूलने पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने बताया कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की निगरानी हिमाचल प्रदेश रेगुलेशन एक्ट, 1997 के तहत की जाती है। इस कानून के तहत निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर नजर रखी जाती है, लेकिन इसमें फीस तय करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान व्यवस्था में निजी स्कूलों की फीस सरकार तय नहीं करती है। हालांकि यदि किसी विधायक या जनप्रतिनिधि के पास ज्यादा फीस वसूलने से जुड़े ठोस मामले हैं तो उनकी जानकारी सरकार को दी जाए, जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिला देना अनिवार्य है।

राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत हैं युवा : राज्यपाल कविंद्र गुप्ता

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है और युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो वे देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वे शुक्रवार को शिमला के गेयटी थियेटर में आयोजित युवा प्रेरणा से राष्ट्र उत्थान विषय पर संगोष्ठी और युवा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। यह कार्यक्रम सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से स्वर्गीय सुनील उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्वलन और स्वर्गीय सुनील उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद संगोष्ठी में वक्ताओं ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, उनके दायित्व और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि भारत एक युवा देश है और अगर युवाओं को सही दिशा और अवसर मिलें तो वे समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि आज के युवाओं में नई सोच, ऊर्जा और बदलाव की क्षमता है। उन्होंने युवाओं से आत्मनिर्भर बनने, नवाचार अपनाने और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की सकारात्मक भागीदारी से ही देश आगे बढ़ सकता है। कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश ठाकुर भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थी जीवन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, इसी समय में जीवन के मूल्य, अनुशासन और सामाजिक चिंतन विकसित होते हैं। उन्होंने युवाओं से समाज की समस्याओं के समाधान में आगे आने और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने का आग्रह किया। इस अवसर पर ट्रस्ट की ओर से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले चार युवाओं को सम्मानित भी किया गया। अर्पण चावला को गौ सेवा और संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। प्रेम लाल को खेल क्षेत्र में उपलब्धियों और अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रशिक्षक के रूप में उनके कार्य के लिए सम्मान दिया गया।

जम्मू एक था है और एक रहेगा : मनीष साहनी

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

जम्मू-कश्मीर इकाई ने पीडीपी ने प्रस्तावित एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन बिल को जम्मू को बांटने की गहरी राजनीतिक साजिश करार देते हुए कड़ा विरोध जताया है। पार्टी के प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि पीडीपी का प्रस्ताव कोई विकास का रोडमैप नहीं है बल्कि जम्मू को तीन टुकड़ों में बांटने की एक सोची-समझी राजनीतिक साजिश है। यह सीधे-सीधे जम्मू की एकता, अस्मिता और राजनीतिक शक्ति पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर घाटी में जनाधार कमजोर होने के बाद पीडीपी अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जम्मू में विभाजनकारी राजनीति कर रही है। साहनी ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृहमंत्री और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे और जब 2014 में महबूबा मुफ्ती सत्ता में थीं, तब उन्हें चिनाब और पीर पंजाल के विकास की याद क्यों नहीं आई उन्होंने आगे कहा कि यदि वास्तव में विकास लक्ष्य होता तो सरकार बुनियादी ढांचे रोजगार, पर्यटन और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के ठोस प्रस्ताव लाती न कि प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्गठन के जरिए राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश करती। साहनी ने उपराज्यपाल के प्रस्ताव की सिफारिश करने पर पूछा कि लोकभवन बताए कि वह जम्मू के विकास के साथ है या विभाजनकारी एजेंडे के साथ शिवसेना ने भाजपा विधायकों से अपील की कि वे विधानसभा में इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करें और आवश्यक हो तो वॉकआउट करें।

अवंतीपोरा पुलिस ने चोरी के दो मामले सुलझाए, आरोपी गिरफ्तार, चोरी की संपत्ति बरामद

अवंतीपोरा। पुलिस स्टेशन अवंतीपोरा की एफआईआर संख्या 62/2026 और 67/2026 के तहत दर्ज दो चोरी के मामलों को पुलिस अवंतीपोरा ने सफलतापूर्वक हल किया। जांच के दौरान पुलिस अवंतीपोरा ने नेतृत्व एसएचओ पीएस अवंतीपोरा इंस्पेक्टर के नेतृत्व में किया गया। आईआईसी पीपी टोल प्लाजा एसआई इश्फाक अहमद के साथ, ऐजाज हमद ने कई स्थानों से सीसीटीवी फुटेज की जांच और विश्लेषण सहित आधुनिक जांच तकनीकों का इस्तेमाल किया। इन प्रयासों से निम्नलिखित आरोपी व्यक्तियों की पहचान हुई और बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई मोहम्मद लतीफ पठान पुत्र मोहम्मद अली पठान निवासी लालीलाब मुजफ्फरी, खानसाहिब, बडगाम, साहिल निसार शेख पुत्र निसार अहमद शेख निवासी अरामपोरा, कमरवारी ने लगातार पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली। चोरी की गई संपत्ति जिसमें दो बछड़े और 1,30,000/- की नकदी (चोरी की आय) शामिल है सफलतापूर्वक बरामद कर ली गई है। उक्त अपराध में शामिल एक अन्य आरोपी की पहचान वसीम शेख के रूप में की गई है और वह फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किये जा रहे हैं

कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय रक्षा कर्मियों हेतु चौथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संपन्न

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ने सब्जी एवं बागवानी फसलों की संरक्षित खेती एवं मूल्य संवर्धन विषय पर 16 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण 8 दिसंबर, 2025 को प्रारंभ हुआ तथा शुक्रवार को प्रसार शिक्षा निदेशालय (डीईई) में सम्पन्न हुआ। यह कार्यक्रम महानिदेशालय पुनर्वास, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित था। प्रशिक्षण में भारतीय सेना के 14 तथा भारतीय नौसेना के 6 जवानों सहित कुल 20 रक्षा कर्मियों ने भाग लिया।

समापन समारोह में प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. विनोद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि मेजर प्रशांत यादव विशिष्ट अतिथि रहे। डॉ. विनोद शर्मा ने प्रतिभागियों की लगन एवं सक्रिय भागीदारी की सराहना की तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस प्रकार के उपयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अर्जित कौशल प्रतिभागियों को कृषि आधारित उद्यम स्थापित करने एवं स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। मेजर प्रशांत यादव ने भी विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण से रक्षा कर्मियों को व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हुआ है, जो उनके सेवानिवृत्ति उपरांत जीवन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुलपति डॉ. ए.के. पांडा ने अपने संदेश में कहा कि इस प्रकार के क्षमता निर्माण कार्यक्रम कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि संरक्षित खेती एवं मूल्य संवर्धन से उत्पादकता, लाभप्रदता तथा उद्यमिता के अवसरों में व्यापक वृद्धि संभव है, विशेषकर प्रशिक्षित रक्षा कर्मियों के लिए। इससे पूर्व पाठ्यक्रम प्रभारी डॉ. लव भूषण ने प्रशिक्षण की रूपरेखा एवं प्रमुख घटकों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, जिसमें संरक्षित खेती की तकनीकों एवं मूल्य संवर्धन पर विशेष बल दिया गया।

वहीं डॉ. अंकुर शर्मा, जिन्होंने

संक्षिप्त-समाचार

जीएमसी अनंतनाग के 3 कर्मचारी लापरवाही के आरोप में निलंबित

अनंतनाग। सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अनंतनाग ने 26 मार्च को हुई एक घटना के बाद मरीजों की देखभाल में लापरवाही के मामले में तीन कर्मचारियों को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में प्रभारी स्टोर कीपर, प्रभारी फार्मासिस्ट और सर्जरी वार्ड में तैनात एक स्टाफ नर्स शामिल हैं। यह कार्रवाई तब की गई जब गंभीर आरोप सामने आए कि मरीजों को एक्सपायर्ड ग्लूकोज दिया गया था जिससे सुरक्षा मानकों को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। एमएमएबीएम एसोसिएटेड अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. अरशद हसन सिद्दीकी ने कहा कि विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है और जल्द से जल्द जिम्मेदार लोगों का निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि संस्थान मरीजों की देखभाल और सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही के प्रति बिल्कुल भी सहनशील नहीं है। इस बीच मरीजों के परिवारकों ने आरोप लगाया कि कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को अंतःशिरा ग्लूकोज दिए जाने के तुरंत बाद प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हुईं। उन्होंने दावा किया कि जाँच करने पर पता चला कि ग्लूकोज की बोतलें लगभग एक साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी थीं। एक अटेंडेंट ने कहा कि यह घोर लापरवाही है और इससे कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

हिमाचल में पंचायत-नगर निकाय चुनाव तक चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर रोक

शिमला। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में पंचायतों और शहरी निकायों के आगामी चुनावों को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देशों की जानकारी देने को कहा है, जिससे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारु रूप से पूरी हो सके। आयोग ने अपने आदेश में बताया है कि उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी (सिविल) संख्या 5451/2026 के निपटारे के दौरान निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 मई 2026 तक पूरे कराए जाएं। इसी निर्देश के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तैयारी तेज कर दी है और मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण सहित कई अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पहले ही शुरू कर दी गई हैं। आयोग का कहना है कि चुनाव से जुड़ी इन गतिविधियों के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की लगातार मौजूदगी और निगरानी जरूरी होती है। ऐसे में अगर इस दौरान उनके तबादले किए जाते हैं तो चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी कारण चुनाव कार्य से सीधे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर फिलहाल रोक लगाई गई है। आयोग ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994, नगर पालिका अधिनियम 1994 और नगर निगम अधिनियम 1994 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार चुनाव से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी चुनाव अवधि के दौरान आयोग के नियंत्रण और अनुशासन के अधीन माने जाते हैं। इसलिए इस अवधि में उनका तबादला बिना आयोग की अनुमति के नहीं किया जा सकता।

जम्मू में एनएलयू की स्थापना को लेकर विधानसभा में भाजपा विधायकों का हंगामा, बजट सत्र बाधित

जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरूआत शुक्रवार को जोरदार हंगामे के साथ हुई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने जम्मू में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) की स्थापना की मांग को लेकर सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। विधायकों ने सरकार से एनएलयू के प्रस्तावित स्थान को लेकर स्पष्टता की मांग की। उनका कहना था कि जम्मू क्षेत्र लंबे समय से उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों से वंचित रहा है, जिससे यहां के छात्रों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इस दिशा में जल्द निर्णय लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा विधायक तख्तियां लेकर सदन में पहुंचे और कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी करने लगे। इस कारण विधानसभा की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। उधर, बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्षी दलों के भी सरकार को घेरने की तैयारी है। विपक्ष राज्य के मुद्दों, चुनावी वादों और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के सवाल पर सरकार से जवाब मांग सकता है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विधानसभा में ऐसे मुद्दों को लेकर और अधिक गर्मा-गर्मी देखने को मिल सकती है, जिससे सत्र के सुचारू संचालन पर असर पड़ सकता है।

चिट्टे के साथ पकड़े हरियाणा के चार युवक भेजे जेल, एक का फिर पुलिस रिमांड

शिमला। राजधानी शिमला में चिट्टे के साथ पकड़े गए हरियाणा के पांच आरोपियों में से चार को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि एक आरोपी का दोबारा पुलिस रिमांड लिया गया है। पुलिस अब मामले के नेटवर्क और चिट्टे की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत अदालत में पेश किया गया था। अदालत से पहले सभी का पांच दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था। इसके बाद चार आरोपियों इरफान, मुकेश, नरेन्द्र और रविकांत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी अंजित का दोबारा पुलिस रिमांड लिया गया है, जिससे मामले की आगे की जांच की जा सके। पुलिस के अनुसार इन पांचों आरोपियों को बीते 19 मार्च को शिमला पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने कार्रवाई करते हुए तारादेवीझ्रटूटू बाईपास क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि एक कार में नशे की खेप लाई जा रही है।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का
न्वोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

हिमाचल में 3 दिन बारिश-बर्फबारी के आसार, आंधी-बिजली की चेतावनी

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में मार्च के अंतिम दिनों में मौसम के तेवर बदल रहे हैं। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 मार्च को प्रदेश में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के आसार जताए हैं। इन तीन दिनों के दौरान कई स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अनुसार इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। शुक्रवार सुबह से ही राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे। इससे तापमान में गिरावट महसूस की गई और ठंड का असर फिर बढ़ गया। ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। लाहौल-स्पीति के केलांग क्षेत्र में ट्रेस (हल्की) बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने आज भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेशभर में मौसम के तेवर ज्यादा खराब रहेंगे। 28 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा, जिसके चलते अगले तीन दिन 28, 29 और 30 मार्च को निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। विभाग ने इन तीन दिनों के लिए कुछ स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 31 मार्च तथा 1 और 2 अप्रैल को भी मौसम खराब रहने की संभावना है, लेकिन इन दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ 28 मार्च की रात से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर हिमाचल में भी देखने को मिलेगा। इस बीच मार्च माह समाप्त होने को है, लेकिन प्रदेश में ठंड का असर अभी भी बना हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों केलांग में आज न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री, कल्पा में 3.5 डिग्री और कुकुमसेरी में 2.6 डिग्री दर्ज किया गया।

श्रीनगर हवाई अड्डे पर अप्रैल से जुलाई के बीच रनवे निर्माण कार्य के कारण उड़ानें रहेंगी प्रतिबंधित

श्रीनगर। भारतीय विमानन प्राधिकरण (एएआई) ने शुक्रवार को बताया कि श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे निर्माण कार्य के कारण अप्रैल से जुलाई के बीच उड़ानें प्रतिबंधित रहेंगी। भारतीय वायु सेना द्वारा जारी एक नोटैम (अधिभोगियों के लिए सूचना) के अनुसार अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू होने वाले रनवे निर्माण कार्य के कारण 6 अप्रैल से 31 जुलाई तक निर्धारित उड़ानों का परिचालन समय अस्थायी रूप से शाम 5 बजे तक सीमित रहेगा। एएआई श्रीनगर ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर यह जानकारी दी। एएआई ने बताया कि वर्तमान में श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे के बीच प्रतिदिन लगभग 60 उड़ानें (आगमन और प्रस्थान) संचालित होती हैं। एएआई ने कहा कि हालांकि परिचालन समय कम किया जाएगा लेकिन डीजीसीए द्वारा अनुमोदित ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के अनुसार उड़ानों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। एयरलाइंस संशोधित समय के अनुसार उड़ानों की योजना बनाएंगी और उनका संचालन करेंगी। एएआई ने कहा कि वह सुरक्षित, कुशल और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एएआई ने यह भी कहा कि इसमें कहा गया है ।

मंडी कलम शिल्प पर आयोजित कार्यशाला संपन्न उपायुक्त ने प्रतिभागियों को किया सम्मानित

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम हिमक्राफ्ट मंडी द्वारा अप्पर बिजनी में मंडी कलम चित्रकला एवं शिल्प पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसका समापन उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और उनका उत्साहवर्द्धन भी किया।

अपूर्व देवगन ने कहा कि युवाओं के कौशल में निखार लाने के लिए सरकार की ओर से विविध स्तर पर प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंडी कलम जैसी लघु चित्रकला शैली पर यह कार्यशाला आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि मंडी नगर अपनी प्राचीन परंपराओं एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन में सदैव अग्रणी रहा है। यहां से उभरी चित्रकला विधा में मंडी कलम उत्तरोत्तर विस्तार पा रही है। इस कला के विकास में युवाओं का योगदान इसे और भी विशेष बना देता है। उन्होंने कहा कि इस विधा के प्रसार की अच्छी संभावनाएं हैं और चित्रकारी में रूचि रखने वालों को इसके लिए निरंतर प्रयास जारी रखते हुए आगे आना चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि एक माह की इस कार्यशाला के दौरान सभी प्रतिभागियों ने बेहद आकर्षक एवं सुंदर पेंटिंग्ज बनाई हैं।

आम लोगों तक उनके इस हुनर को ले जाने के लिए आयोजकों की पहल पर इसकी एक प्रदर्शनी लगाने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस तरह के कार्यक्रमों को मूर्तरूप प्रदान करने तथा ललित कला को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन हमेशा कलाकारों एवं कारीगरों के साथ है। उन्होंने मंडी कलम को प्रोत्साहन देने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम (हिमक्राफ्ट) के प्रयासों की भी सराहना की।

राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला संपन्न, कुलदीप सिंह पठानिया ने की शोभा यात्रा में शिरकत

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

मंडी जिला के सुंदरनगर में चैत्र नवरात्रों के उपलक्ष्य में आयोजित पांच दिवसीय राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला शुक्रवार को विधिवत सम्पन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की। इस अवसर पर उन्होंने महामाया मंदिर में देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की तथा महामाया मंदिर से जवाहर पार्क मेला मैदान तक निकली भव्य शोभायात्रा में भाग लिया। नवमी के अवसर पर कृषक प्रशिक्षण केंद्र के कम्युनिटी हॉल में कंजक पूजन भी किया गया। कुलदीप सिंह पठानिया ने मेले के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया और इसे सराहनीय पहल बताया। उन्होंने मेले में पधारे देवी-देवताओं को चादरें व नजराना भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को सुकेत देवता मेला की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि इन परंपराओं को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखना आवश्यक है, क्योंकि यही हमारी पहचान को सशक्त बनाती हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की संस्कृति अपनी सरलता, ईमानदारी और परंपराओं के संरक्षण के लिए पूरे देश में विशेष स्थान रखती है।

अपील | प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील

विधानसभा में उमर अब्दुल्ला ने ईरान युद्ध को बताया 'अन्यायपूर्ण और अवैध'

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में ईरान पर थोपे गए अन्यायपूर्ण और अवैध युद्ध की कड़ी निंदा की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की कि वे मानवता के हित में इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपने प्रभाव और कूटनीतिक संबंधों का उपयोग करें।

यह बयान उस समय आया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सदस्यों ने इस मुद्दे पर सदन में आधिकारिक प्रतिक्रिया देने का दबाव बनाया। हालांकि, भाजपा विधायकों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ईरान से जुड़ा संकट एक अंतरराष्ट्रीय मामला है और यह विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

सदन के नेता के रूप में बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे अपनी पार्टी और सहयोगियों की ओर से इस युद्ध की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और इस संघर्ष में जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जैसे प्रभावशाली देश को शांति स्थापित करने में भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे सभी उपलब्ध राजनयिक माध्यमों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का इस्तेमाल कर इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त कराने की दिशा में प्रयास करें। अब्दुल्ला ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि इस संघर्ष का असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त होने से न केवल प्रभावित देशों को राहत मिलेगी, बल्कि पूरी मानवता को इसका लाभ होगा। विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच मतभेद भी देखने को मिले, लेकिन अंततः मुख्यमंत्री ने शांति और कूटनीति के जरिए समाधान पर जोर दिया।

महबूबा मुफ़्ती ने उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना, ईरान मुद्दे पर उनके देर से आए बयान को बताया निराशाजनक

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को ईरान पर इजरायल के हमले की निंदा करने में देरी को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आलोचना की। उन्होंने इस देरी को निराशाजनककरार दिया। दरअसल, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज विधानसभा में ईरान पर थोपे गए अन्यायपूर्ण और अवैध युद्धकी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की थी कि वे मानवता के हित में इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। अपने बयान में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे और उनके सहयोगी इस युद्ध की कड़ी निंदा करते हैं तथा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और इस संघर्ष में जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसी बीच, महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि यह बेहद निराशाजनक है कि भारत के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री को ईरान पर इजरायल के घृणित हमलेकी स्पष्ट निंदा करने में लगभग एक महीना लग गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब विधानसभा ने इस मामले में तेजी से कार्रवाईकरते हुए ईरान के समर्थन और हमले की निंदा का प्रस्ताव पारित किया, जबकि जम्मू-कश्मीर सरकार ऐसा करने में पीछे रह गई। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस गंभीर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर न तो तत्परता दिखाई और न ही कोई ठोस कदम उठाया। उनके अनुसार, सरकार की प्रतिक्रिया केवल बयानबाजी और भाषणों तक सीमित रही, जबकि इस मुद्दे पर स्पष्ट और सिद्धांत आधारित रुख अपनाने की आवश्यकता थी।

गेहूं बेचने में किसानों को नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार की परेशानी: डॉ. साकेत कुमार

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार ने किया कैथल मंडी का दौरा, खरीद सीजन की तैयारियों का लिया जायजा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं जिला कैथल के प्रशासनिक सचिव डॉ. साकेत कुमार ने कहा कि रबी सीजन के दौरान गेहूं व अन्य फसलों की खरीद को समुचित रूप से की जाए। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने गेहूं खरीद के लिए जो भी नए प्रावधान किए हैं, उनके पालन के लिए सभी मंडियों में व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। मंडियों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। बारदाने की पूरी व्यवस्था की जाए और फसल खरीद के बाद उसका समयबद्ध उठान किया जाए, ताकि मंडी में जाम जैसी स्थिति पैदा न हो।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार शुक्रवार को अनाज मंडी कैथल में अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक के बाद उन्होंने मंडी का दौरा भी किया। साथ ही आढ़तियों की समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने गेहूं खरीद की तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की। इस दौरान डीसी अपराजिता व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि सभी उपकरणों को समयबद्ध दुरूस्त करवाएं। इस कार्य में कोई भी लापरवाही न बरती जाए। गेट पास के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त ली। जिसमें नए प्रावधान के तहत मंडी में प्रवेश के समय किसानों की फोटो खिंचने से लेकर बायोमीट्रिक तक एवं बाद में एजेंसी के रिकॉर्ड में इंद्राज तक की पूरी प्रक्रिया की बारीकी से समीक्षा की। इन विभिन्न चरणों में आवश्यक संसाधनों प्रिंटर, नमी मापने के यंत्र, बारदाना, कर्मचारियों की संख्या, गोदामों में खाली जगह, डिजिटल धर्मकांटों सहित सभी तरह के स्टॉक के बारे में जानकारी ली और आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया इतने सरल तरीके से हो कि किसानों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि मंडियों की आवाजाही में किसानों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए मंडी की सड़क को दुरूस्त करवाएं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंडी अधिकारियों व आढ़तियों से भी बातचीत की और उन्हें खरीद सीजन के दौरान सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीने का पानी, बिजली, साफ-सफाई, लोडिंग व अनलोडिंग की सुचारू व्यवस्था में लापरवाही न बरती जाए और किसानों की फसल को निर्धारित मापदंड अनुसार ही खरीदा जाए। उन्होंने आढ़तियों की समस्याएं भी सुनीं और उनके समाधान का आश्वासन दिया। डीसी अपराजिता ने फसल खरीद प्रक्रिया की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा। इस मौके पर डीएमईओ अभिनव वालिया, मार्किट कमेटी सचिव नरेंद्र ढुल, विजेंद्र, रोहित एवं रमन के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

जनभागीदारी से पानीपत बनेगा हरियाणा का सबसे हरा-भरा शहर: विपुल गोयल

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- विपुल गोयल का आह्वान: उद्योगपति आय का 2 प्रतिशत पर्यावरण संरक्षण पर करें खर्च
- ग्रीन पानीपत मिशन को नई उड़ान, 3 लाख पौधारोपण का लक्ष्य तय

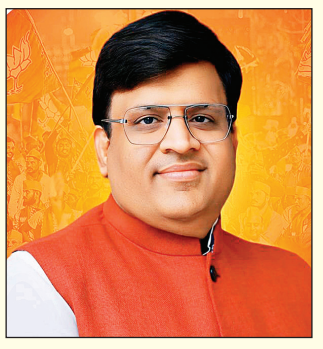

हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री विपुल गोयल ने ग्रीन पानीपत मिशन के तहत शुक्रवार को औद्योगिक सेक्टर-29 पार्ट-2 में पौधारोपण कर अभियान को नई गति प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं, निगम प्रशासन और विभिन्न सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसमें सभी वर्गों की भागीदारी अनिवार्य है।

उन्होंने औद्योगिक घरानों से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे अपनी आय का कम से कम 2 प्रतिशत हिस्सा पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों पर खर्च करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि उद्योगों के सहयोग से यह अभियान और अधिक प्रभावी बन सकता है। मंत्री ने बताया कि पिछले 16 महीनों में पानीपत के विकास के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है।

श्री विपुल गोयल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान समाज में सकारात्मक संदेश दे रहे हैं और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी स्वयं लें।

मंत्री ने कहा कि पौधारोपण केवल एक दिन का कार्य नहीं है, बल्कि इसके संरक्षण और पोषण पर लगातार ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि लगाए गए पौधों की कम से कम तीन वर्षों तक नियमित देखभाल की जाए, ताकि वे पूर्ण विकसित हो सकें। उन्होंने कहा कि यदि हम आज पौधों की देखभाल करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और पूरा पानीपत स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त शहर के रूप में विकसित होगा। उन्होंने सफाई अभियान की सफलता का उल्लेख करते हुए विश्वास जताया कि ग्रीन पानीपत मिशन भी उसी तरह सफल होगा। छोटे-छोटे पार्कों को विकसित कर उन्हें मिनी वन का रूप देने की भी बात कही, जिससे शहर में हरित क्षेत्र का विस्तार हो सके।

हरियाणा में गैस और डीजल संकट पर सरकार की विफलता उजागर: सैलजा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- जनता को राहत देने में नाकाम भाजपा सरकार, तुरंत समाधान किया जाए
- प्रदेश में एलपीजी की किल्लत बढ़ गई है और लोगों को सिलेंडर लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है

सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी सैलजा ने हरियाणा में एलपीजी, पीएनजी और डीजल संकट को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिना तैयारी के पीएनजी को अनिवार्य करने के फैसले ने जनता को परेशानी में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को एलपीजी कनेक्शन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन पीएनजी कनेक्शन समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे हजारों परिवार गैस सुविधा से वंचित हो गए हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी लाइन मौजूद है, वहां भी बड़ी संख्या में आवेदन लंबे समय से लंबित हैं, जो सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में एलपीजी की किल्लत बढ़ गई है और लोगों को सिलेंडर लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने डीजल संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं और कई जगहों पर डीजल खत्म हो रहा है, जिससे किसानों को भारी परेशानी हो रही है, खासकर गेहूं की कटाई के समय। कुमारी सैलजा ने सरकार से मांग की कि एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, पीएनजी कनेक्शन प्रक्रिया को तेज किया जाए और किसानों के लिए डीजल की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाए।

जीएमडीए स्टॉर्म वॉटर ड्रेन और सीवरेज लाइन की सफाई के लिए एसओपी तैयार करे: योगेश कुमार

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव योगेश कुमार ने ली बैठक, यमुना को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने पर जोर
- सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश

हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री योगेश कुमार ने यमुना को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष निर्देश दिए है। गुरुग्राम में चल रहे कार्यों को और गति देने के लिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव योगेश कुमार ने शुक्रवार को विकास सदन में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान ड्रेनों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए तैयार कार्ययोजना की विस्तार से समीक्षा की गई।

सदस्य सचिव श्री योगेश कुमार ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के अधिकारियों से कार्य प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट लेने के उपरांत निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करते हुए जमीन पर प्रभावी परिणाम सुनिश्चित किए जाएं।

अधिकारी श्री योगेश कुमार ने नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारियों से उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों बारे भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि नए पंजीकृत टैंकरों की विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए तथा अवैध टैंकर संचालन पर सख्त कार्रवाई के लिए विशेष टीम का गठन किया जाए।

साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि ड्रेनों के किनारे किए जा रहे फेंसिंग कार्य की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि अवैध प्रवेश और कचरा फेंकने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही सभी एसटीपी का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा उनके संचालन को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए रखने बारे भी निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि ड्रेनों की टेपिंग, एसटीपी और सीईटीपी की स्थापना, प्रभावी कचरा प्रबंधन तथा निगरानी तंत्र को मजबूत किए जाने से यमुना के जल की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो रही है। श्री योगेश कुमार ने निर्देश दिए कि सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि प्रदूषण नियंत्रण के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सके।

बैठक में सीईई, एचएसपीसीबी श्री बलराज अहलावत, सीई एमसीजी श्री विजय ढाका (लेग-1 के नोडल अधिकारी), एसईई एचएसपीसीबी श्री जतिंदर पाल, सीनियर मैनेजर एचएसआईआईडीसी श्री संजय कुमार, एसीपी ट्रैफिक श्री सत्यपाल, आरओ, एचएसपीसीबी (गुरुग्राम रीजन-उत्तर) आकांक्षा तंवर, ईई जीएमडीए श्री विक्रम (लेग-2 व लेग-3 के नोडल अधिकारी), ईई एमसीजी श्री प्रदीप, ईई जीएमडीए श्री पारिक गर्ग, ईई सिंचाई विभाग झज्जर श्री पुनीत साहनी, ईई सिंचाई विभाग गुरुग्राम श्री जितेंद्र सिंह तथा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार एसईएसटीएफ के सदस्य भी मौजूद रहे।

संक्षिप्त-समाचार

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हुई डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की शिष्टाचार भेंट

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी की शिष्टाचार भेंट हुई। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सपरिवार बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भेंट के दौरान आध्यात्मिक एवं सामाजिक विषयों पर संक्षिप्त चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री ने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के समाज में सद्भावना और नैतिक मूल्यों के प्रसार में योगदान की सराहना की। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई।

जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने किया 9 परिवादों का समाधान

चंडीगढ़। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय, सत्कार, वास्तुकला मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी की अध्यक्षता में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक यमुनानगर जिला सचिवालय के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में 15 परिवाद रखे गए, जिनमें से कैबिनेट मंत्री ने 9 परिवादों को मौके पर ही समाधान करके फाइल कर दिया तथा शेष 6 परिवादों को आगामी बैठक तक हल करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने जिन 9 परिवादों का मौके पर ही निपटान करके फाइल करने के निर्देश दिए, जिनमें परिवाद नम्बर-2 में गांव गधौली निवासी राजिन्द्र सिंह ने चतंग नदी पर पटरी से मिट्टी हटाने बारे, परिवाद नम्बर-3 में गांव भवानीपुर निवासी अनुज ने संजीव कुमार सरपंच व रणबीर सिंह के खिलाफ पंचायती पेड़ काटने की शिकायत दी जिस पर कैबिनेट मंत्री ने वन विभाग को निर्देश दिए कि इस संबंध में नोटिस दें और कटे पेड़ की रिकवरी कर पंचायत में जमा करें, परिवाद नम्बर-4 में याकुबपुर निवासी जीतो ने पिछली बैठक में घर के आंगन में से ट्रांसफार्मर हटवाए जाने बारे शिकायत दी जिस पर कैबिनेट मंत्री ने बिजली विभाग को निर्देश दिए थे कि ट्रांसफार्मर हटवाएं, बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर को हटवा दिया, जिसके लिए जितो ने ट्रांसफार्मर हटवाए जाने पर कैबिनेट मंत्री का धन्यवाद किया।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल

चंडीगढ़। हरियाणा में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने, कृषि क्षेत्र के उत्थान, आवासीय व इंडस्ट्रियल (कमर्शियल) क्षेत्र को लाभान्वित करने की दिशा में अलग-अलग विभाग और एजेंसियां तेजी से काम कर रही हैं। इनमें डीएनआरई, हरेडा के अलावा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हैं। उत्तर हरियाणा बिजली निगम के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जबकि सोलर पंप की इंस्टॉलेशन के मामले में महाराष्ट्र के बाद देश भर में दूसरा स्थान हासिल करने वाला राज्य बना है। हालांकि, हरियाणा में 2026-27 तक 2.2 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय किया गया है. पीएम-सूर्य घर योजना के तहत अब तक राज्य में 61875 रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके है। प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में किसान, आम व्यक्ति और उद्योगपति हर कोई सौर ऊर्जा के माध्यम से भारी भरकम बिजली बिल की बचत, ग्रिड को अतिरिक्त बिजली यूनिट बेचने और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से आर्थिक लाभ अर्जित कर रहे है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र की पीएम-सूर्य घर योजना के साथ साथ हरियाणा की राज्य सरकार भी अतिरिक्त सब्सिडी के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों और विशिष्ट श्रेणियों को अतिरिक्त धनराशि का लाभ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना भी लाई गई है जिसके तहत आवासीय उपभोक्ताओं को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नतीजतन बिजली बिल में 90 प्रतिशत तक की कमी और 25 साल तक मुफ्त बिजली मिलती है।

2 करोड़ 23 लाख के बजट से कुरुक्षेत्र में होंगे विकास काय: कंवलजीत कौर

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

जिला परिषद चेयरपर्सन कंवलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश चहुंमुखी विकास पथ पर है, बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य लगातार किए जा रहे है तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। जिला परिषद चेयरपर्सन शुक्रवार को पंचायत भवन के सभागार में जिला परिषद की 127वीं बैठक को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने बताया कि जिला परिषद के पास 2 करोड़ 23 लाख का बजट उपलब्ध था, इस बजट को आज की बैठक में स्वीकृति सदस्यों की सहमति दी गई और इस बजट से विकास कार्य जल्द ही करवाए जाएंगे, जो विकास कार्य करवाए जाएंगे उनकी सूची तैयार कर ली गई है। इस बजट में टाइड के लिए लगभग 1 करोड़ 34 लाख और अनटाइड में करीब 89 लाख शामिल है।

उन्होंने बताया कि टाइड के बजट में से पीने के पानी से सम्बन्धित और स्वच्छता से सम्बन्धित विकास कार्य करवाए जाएंगे तथा अनटाइड के बजट में विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के बारे में सभी सदस्यों से कहा कि अपने अपने क्षेत्र में इस योजना का प्रचार प्रसार करे ताकि आम जन इस योजना का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना सहित कई जनकल्याणकारी योजनाओं का आमजन को सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। जिला परिषद चेयरपर्सन ने इस बात की भी स्वीकृति सदस्यों से ली कि अगर कोई बजट आगामी माह के अंत तक आता है तो उसे भी आज की बैठक में शामिल किया जाएगा और इससे भी विकास कार्य करवाए जाएंगे।

जिला परिषद के वाईस चेयरमैन धर्मपाल चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में पेंशन में बढ़ोतरी की है जिसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार प्रकट किया और कहा कि जिला परिषद के पास बजट की कमी नहीं है और प्राथमिकता के आधार पर जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जा रहे है। इससे पहले जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शम्भू राठी ने सभी सदस्यों के सामने बैठक के एजेंडे के बारे में विस्तार से बताया और आए हुए सदस्यों का स्वागत भी किया। इस मौके पर जिला परिषद के डिप्टी सीईओ कृष्ण लाल, लेखा अधिकारी सत्य भूषण सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के विद्यार्थियों की उपलब्धियां कुवि के लिए गर्व का विषय: प्रो. सोमनाथ सचदेवा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियां संस्थान की गुणवत्ता, समर्पण और सतत प्रयासों का प्रमाण हैं। विद्यार्थियों की सफलता अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का कार्य करती है तथा उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उद्गार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने विश्वविद्यालय के इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के दो मेधावी विद्यार्थियों के प्रतिष्ठित गेट- 2026 परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत हर्ष एवं गर्व का विषय है कि इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के दो विद्यार्थियों समर्थ और आकाश (बी.टेक) ने गेट- 2026 परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने न केवल विभाग का नाम गौरवान्वित किया है, बल्कि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत प्रस्तुत किया है।

इस अवसर पर विभागाध्यक्ष प्रो. अवनीश वर्मा ने बताया कि हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (एचएससीएसआईटी), पंचकुला की ओर से विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट कार्यों के लिए 71,500 की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। यह सहयोग विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा उन्हें नवीन और नवाचारपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।

प्रो. अवनीश वर्मा ने बताया कि यह सभी उपलब्धियां विभाग के निरंतर प्रयासों, शिक्षकों के मार्गदर्शन और विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत का परिणाम हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर रहने के लिए प्रतिबद्ध है तथा विद्यार्थियों को शोध, नवाचार और तकनीकी दक्षता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा। विभाग के शिक्षकों ने भी दोनों विद्यार्थियों को इस सफलता पर हार्दिक बधाई दी गई तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर डीन प्रो. संजीव अग्रवाल, प्रो. दिनेश राणा, प्रो. सुरेन्द्र, प्रो. विवेक चावला मौजूद रहे।

अभिनेता अजय जेठी ने मजदूरी से मनी हिस्ट के शकीर तक के किरदार के अनुभव किए साझा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

- स्पेनिश सिनेमा में संघर्ष और सफलता की कहानी की बंया

किरदार स्क्रीन पर दिखता है, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स नहीं। कलाकार की असली पहचान और काबिलियत उस काम से होती है जो आप करते हो जैसे एक्टिंग, स्किल, मेहनत ना कि सोशल मीडिया की प्रसिद्धि से। आजकल लोग अक्सर फॉलोअर्स, लाइक्स और व्यूज को सफलता का पैमाना मान लेते हैं, लेकिन जब बात असली काम (जैसे फिल्म, सीरीज, या किसी भी प्रोफेशन) की आती है, तो वहां सिर्फ आपका टैलेंट और किरदार ही मायने रखता है। यह विचार अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय अभिनेता अजय जेठी ने 8वें हरियाणा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गुरुवार को एक विशेष साक्षात्कार के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने अपनी फिल्मी यात्रा और फिल्म जगत की चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की। नेटफ्लिक्स की विश्व प्रसिद्ध वेब सीरीज मनी हिस्ट में शकीर के किरदार से वैश्विक पहचान बनाने वाले अजय जेठी ने भारत से स्पेन तक के अपने सफर के उन पहलुओं को उजागर किया, जो अक्सर चकाचौंध के पीछे छिपे रह जाते हैं।

अभिनेता अजय ने बताया कि वे बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन के छात्र थे, जब उन्होंने रंगमंच (थिएटर) की दुनिया में कदम रखा। अभिनय के प्रति उनके जुनून ने उन्हें पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिससे उनके पिता काफी नाराज थे। उस दौर में पंजाब में सिनेमा का भविष्य अनिश्चित था, जिसके चलते उन्हें स्पेन जाने का फैसला लेना पड़ा। स्पेन की शुरूआती यात्रा अजय के लिए आसान नहीं थी। उन्होंने शुरूआत में कंस्ट्रक्शन लेबर, दुकानों और फैक्ट्रियों में मजदूरी की। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सबसे पहले स्पेनिश भाषा पर पकड़ बनाई। 2008-09 में मिली पहली स्पेनिश फिल्म ने उनके लिए सफलता के द्वार खोल दिए।

सुमिता मिश्रा ने कई सरकारी मेडिकल कालेजों के प्रगति की समीक्षा की

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, डॉ. सुमिता मिश्रा ने शुक्रवार को राज्य के कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों की प्रगति की समीक्षा की और काम करने वाली एजेंसियों को समय-सीमा का पालन करने और अटके हुए कामों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने और एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ जनता को आसानी से उपलब्ध टर्शियरी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

डॉ. सुमिता मिश्रा चंडीगढ़ में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निगरानी और पर्यवेक्षी समिति की 30वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सिविल कार्यों को समय-सीमा के भीतर पूरा करना, उपकरणों की खरीद करना और फैकल्टी की भर्ती करना सुनिश्चित करें। कैथल और यमुनानगर में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज, जो दोनों ही लगभग 80 प्रतिशत पूरे हो चुके हैं, को 30 जून, 2026 की डेडलाइन दी गई है।

डॉ मिश्रा ने अधिकारियों से कहा कि वे बायोमेडिकल उपकरणों और फर्नीचर की खरीद शुरू करें, और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से सभी जरूरी मंजूरी प्राप्त करें, ताकि वर्ष 2027-28 के शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस में दाखिले शुरू किए जा सकें। बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि जींद स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में, जहाँ संशोधित वित्तीय अनुमानों की मंजूरी अटकी होने के कारण निर्माण कार्य धीमा हो गया है, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे वित्त विभाग के साथ इस मामले का फॉलो-अप करें।

सिरसा स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज, जो अभी लगभग 35 प्रतिशत पूरा हुआ है, के लिए 31 मार्च, 2027 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में साइट पर पीने के पानी की आपूर्ति और तूफानी पानी के प्रबंधन से संबंधित चिंताओं पर भी प्रकाश डाला गया। डॉ. सुमिता मिश्रा ने निर्देश दिया कि इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल किया जाए। बैठक में यह भी बताया गया कि कुटेल, करनाल स्थित पं. दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर पूरा हो चुका है, जबकि निजी वार्ड प्रोजेक्ट–जिसकी अनुमानित लागत 30.45 करोड़ रुपये है, पर काम अभी लगभग 30 प्रतिशत ही हुआ है। काम करने वाली एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि वे 30 सितंबर, 2026 की डेडलाइन को पूरा करने के लिए निर्माण कार्य में तेजी लाएँ।

तीन संस्थानों के लिए , स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुटेल , पं. नेकी राम शर्मा सरकारी मेडिकल कॉलेज भिवानी और महर्षि च्यवन सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोरियावास में, जहाँ 2025-26 सत्र के लिए 100 एमबीबीएस छात्र पहले ही दाखिला ले चुके है , यह निर्णय लिया गया कि मूल उपकरण निमार्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए, ताकि रखरखाव के कार्यों का ठेका दिया जा सके। इन कार्यों में एचवीएसी सिस्टम, लिफ्ट, डीजी सेट, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन और जल उपचार संयंत्र जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं को शामिल किया जाएगा; विशेष रूप से तब, जब इन उपकरणों की 'दोष दायित्व अवधि' समाप्त होने वाली हो।

खानपुर कलां (सोनीपत) स्थित भगत फूल सिंह सरकारी महिला मेडिकल कॉलेज और करनाल स्थित कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज में चल रहे विस्तार कार्यों की भी समीक्षा की गई, और उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। डॉ. मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाने चाहिए, ताकि नए मेडिकल कॉलेज बिना किसी देरी के पूरी तरह से चालू हो सकें।

संपादकीय

सरकार का बड़ा फैसलाः पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम, पर जनता को कितनी राहत?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच भारत सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का निर्णय एक अहम आर्थिक और राजनीतिक कदम माना जा रहा है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव लगातार बना हुआ है और इसका असर आयात-निर्भर देश पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस फैसले का सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा या यह राहत सीमित ही रह जाएगी। भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल आयात करने वाले देशों में से एक है। देश अपनी कुल जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत तेल विदेशों से मंगाता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाली किसी भी हलचल का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है। हाल के महीनों में भू-राजनीतिक तनाव, तेल उत्पादक देशों द्वारा उत्पादन में कटौती और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। इस स्थिति ने भारत सरकार के सामने महंगाई को नियंत्रित करने और आम जनता को राहत देने की चुनौती खड़ी कर दी। इसी दबाव के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कमी करने का फैसला लिया। यह कदम महंगाई को काबू में रखने और परिवहन लागत को कम करने की दिशा में उठाया गया है। चूंकि ईंधन की कीमतों का असर सीधे तौर पर वस्तुओं और सेवाओं की लागत पर पड़ता है, इसलिए इसमें थोड़ी भी कमी से व्यापक आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद की जाती है। हालांकि, इस फैसले के बाद भी यह स्पष्ट नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कितनी गिरावट आएगी। भारत में ईंधन की कीमत कई घटकों पर निर्भर करती है। इसमें कच्चे तेल की कीमत, रिफाइनिंग खर्च, परिवहन लागत, डीलर कमीशन और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए टैक्स शामिल हैं। एक्साइज ड्यूटी में कटौती केवल केंद्रीय कर का हिस्सा कम करती है, जबकि राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला वैट अभी भी कीमतों पर बड़ा प्रभाव डालता है। यही कारण है कि यदि राज्य सरकारें अपने स्तर पर वैट में कमी नहीं करतीं, तो उपभोक्ताओं को सीमित राहत ही मिल सकती है। इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियां भी कीमतों को तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं। ये कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, अपने मुनाफे और पिछले घाटे को ध्यान में रखते हुए कीमतों को समायोजित करती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि वैश्विक कीमतों में गिरावट के बावजूद घरेलू कीमतों में तुरंत कमी नहीं की जाती, क्योंकि कंपनियां पहले अपने नुकसान की भरपाई करती हैं। सरकार के इस फैसले के सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो सबसे पहले यह महंगाई पर नियंत्रण के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ईंधन की कीमतें कम होने से परिवहन लागत घटती है, जिससे खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी दबाव कम पड़ता है। इससे आम आदमी की जेब पर बोझ कम हो सकता है। इसके अलावा, यह कदम आर्थिक गतिविधियों को भी गति देने में सहायक हो सकता है। जब ईंधन सस्ता होता है, तो उद्योगों की लागत घटती है और उपभोक्ता खर्च में भी वृद्धि होती है। इससे समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार अक्सर ऐसे कदम उठाकर यह संदेश देने की कोशिश करती है कि वह आम जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। खासकर ऐसे समय में जब महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है, ईंधन की कीमतों में राहत देना एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है। हालांकि, इस फैसले के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से सरकार के राजस्व में कमी आती है। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स सरकार के लिए आय का एक बड़ा स्रोत हैं। इनसे मिलने वाला राजस्व विभिन्न विकास परियोजनाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ऐसे में टैक्स में कटौती का असर सरकारी वित्तीय संतुलन पर पड़ सकता है। इसके अलावा, यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, तो सरकार के लिए लंबे समय तक इस तरह की राहत देना संभव नहीं रहेगा। भविष्य में फिर से टैक्स बढ़ाने या कीमतों में वृद्धि की स्थिति बन सकती है, जिससे उपभोक्ताओं पर दोबारा बोझ पड़ सकता है। दीर्घकालिक समाधान की बात करें तो भारत को अपनी ऊर्जा नीति में व्यापक बदलाव करने की आवश्यकता है। तेल आयात पर अत्यधिक निर्भरता देश को वैश्विक अस्थिरताओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। ऐसे में सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना और घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ाने जैसे कदमों पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही, ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने की जरूरत है, ताकि उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट रूप से समझ में आ सके कि कीमतों में बदलाव किन कारणों से हो रहा है। इससे विश्वास बढ़ेगा और बाजार में अनिश्चितता कम होगी। अंततः, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती एक सकारात्मक कदम जरूर है, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जब तक केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर समन्वित प्रयास नहीं करतीं और तेल कंपनियां पारदर्शी तरीके से कीमतों में बदलाव नहीं करतीं, तब तक आम जनता को पूर्ण राहत मिलना कठिन है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वास्तविक कमी देखने को मिलती है या नहीं। यदि यह कटौती सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, तो यह न केवल महंगाई को कम करने में मददगार होगी, बल्कि देश की आर्थिक गति को भी मजबूती देगी।

अदालत की कसौटी में स्थानांतरण नीति

डॉ. सत्यवान सौरभ (हि.स)

हरियाणा की स्थानांतरण नीति पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी ने एक गंभीर और दूरगामी संवैधानिक बहस को जन्म दिया है। यह बहस केवल एक प्रशासनिक निर्णय या अंक-प्रणाली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस मूल प्रश्न को छूती है जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्र में होता है–समानता का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना ही समानता है, या परिस्थितियों के अनुसार भिन्न व्यवहार ही न्याय के अधिक निकट है? जनवरी 2026 में आई टिप्पणी ने हरियाणा सरकार की स्थानांतरण नीति 2025 को व्यापक सार्वजनिक विमर्श का विषय बना दिया। इस नीति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 40-60 प्रतिशत दिव्यांगता पर 10 अंक, 60-80 प्रतिशत पर 15 अंक तथा 80 प्रतिशत से अधिक पर 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रथम दृष्टि में यह व्यवस्था तर्कसंगत और संवेदनशील प्रतीत होती है, क्योंकि यह इस मूल तथ्य को स्वीकार करती है कि दिव्यांगता एकरूप नहीं होती, बल्कि उसकी तीव्रता और प्रभाव भिन्न-भिन्न होते हैं। इस दृष्टि से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को अधिक सहायता देना न्यायसंगत माना जा सकता है।

किन्तु यहीं से विवाद का प्रारंभ होता है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसा वर्गीकरण संवैधानिक कसौटियों पर खरा उतरता है? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस नीति को निरस्त नहीं किया है, बल्कि इसके औचित्य पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला गहन विचारणीय है और इसमें संवैधानिक सिद्धांतों की सूक्ष्म समीक्षा अपेक्षित है।याचिकाकर्ताओं का तर्क मुख्यतः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 पर आधारित है। इस अधिनियम के अनुसार 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्ति एक समान श्रेणी में आते हैं। ऐसे में 40 और 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के बीच अंक-आधारित भेदभाव समानता के अधिकार का उल्लंघन प्रतीत हो सकता है। यह दृष्टिकोण 'औपचारिक समानता' की अवधारणा को रेखांकित करता है, जिसमें सभी के साथ समान व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।

हालांकि, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 केवल औपचारिक समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि 'वास्तविक समानता' की ओर संकेत करता है। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार जैसे मामलों में 'तर्कसंगत वर्गीकरण' का सिद्धांत स्थापित किया है।

इसके अनुसार, यदि वर्गीकरण स्पष्ट, बुद्धिसंगत और उद्देश्य से तार्किक रूप से जुड़ा हो, तो वह असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। यहीं यह प्रश्न और जटिल हो जाता है कि क्या दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर किया गया यह वर्गीकरण वास्तव में तर्कसंगत है। क्या 40 और 80 प्रतिशत दिव्यांगता के बीच का अंतर केवल संख्यात्मक है, या यह व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता, कार्यक्षमता और आत्मनिर्भरता में भी गहरा अंतर उत्पन्न करता है? यदि यह अंतर वास्तविक है, तो अधिक अंक देना न्यायोचित ठहराया जा सकता है; अन्यथा यह वर्गीकरण मनमाना प्रतीत होगा।

दिव्यांगता को केवल चिकित्सीय दृष्टि से समझना पर्याप्त नहीं है; यह एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अनुभव भी है। किसी व्यक्ति की कार्यक्षमता, सामाजिक सहभागिता और आत्मनिर्भरता–ये सभी कारक उसकी वास्तविक स्थिति को निर्धारित करते हैं। अतः केवल प्रतिशत के आधार पर नीति निर्माण एक सीमित और अधूरा दृष्टिकोण हो सकता है। इसके साथ ही, नीति की पारदर्शिता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान विवाद का एक प्रमुख कारण यह है कि अंक निर्धारण के पीछे का वैज्ञानिक या सांख्यिकीय आधार स्पष्ट नहीं किया गया है। यदि यह आधार सार्वजनिक नहीं होगा, तो नीति मनमानी प्रतीत हो सकती है, चाहे उसका उद्देश्य कितना ही सकारात्मक क्यों न हो।

इस संदर्भ में न्यायालय का हस्तक्षेप एक रचनात्मक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नीतियां केवल औपचारिक न रह जाएं, बल्कि वास्तविक न्याय का माध्यम बनें। यह लोकतंत्र की वह शक्ति है, जहां न्यायपालिका नीतियों को संतुलित और उत्तरदायी बनाए रखती है।

सरकार के लिए यह आत्ममंथन का उपयुक्त समय है। यदि अंक निर्धारण के पीछे ठोस शोध और आंकड़े हैं, तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यदि नहीं, तो विशेषज्ञों की एक बहु-विषयक समिति गठित कर अधिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए। केवल प्रतिशत के स्थान पर 'कार्यात्मक क्षमता', 'दैनिक जीवन पर प्रभाव' और 'सामाजिक सहभागिता' जैसे मानकों को शामिल करना अधिक न्यायसंगत दृष्टिकोण हो सकता है।

अंततः, यह बहस हमें समानता की अवधारणा पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है। समानता का अर्थ सबको एक जैसा देना नहीं, बल्कि सबको उनकी परिस्थितियों के अनुरूप न्याय देना है। यही वास्तविक समानता है, जो एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला बनती है। निष्कर्षतः, यह मुद्दा सरकार और न्यायालय के बीच टकराव का नहीं, बल्कि नीति और न्याय के संतुलन का है। यदि हरियाणा सरकार संवेदनशीलता और तर्क के बीच संतुलन स्थापित कर पाती है, तो यह केवल एक विवाद का समाधान नहीं होगा, बल्कि भविष्य की नीतियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण सिद्ध होगा।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

एचपीवी टीकाकरणः लड़कियों के लिए एक साधारण सा टीका सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन की दिशा में बहुत बड़ा कदम

नीरजा भटला

प्रोफेसर हैराल्ड जुर हाउजेन को 2008 में उनकी इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला कि ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) के हाई-रिस्क स्ट्रेन से लगातार होने वाला संक्रमण ही सर्वाइकल कैंसर का मूलभूत कारण है। यह दुनिया भर में रुग्णता और मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन कम और निम्न-मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में इसका प्रभाव अधिक है। उनकी इस खोज ने रोगनिरोधी टीकों के साथ-साथ संक्रमण फैलाने वाले एजेंट का पता लगाने वाले परीक्षणों के विकास का भी मार्ग प्रशस्त किया। एक दशक बाद, 2018 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन की दिशा में एक पहल की घोषणा की, और 17 नवंबर 2020 को इस संबंध में एक वैश्विक रणनीति औपचारिक रूप से शुरू की गई, जिसे भारत सहित 194 देशों ने समर्थन दिया।

कैंसर का उन्मूलन! वह भी कोई साधारण कैंसर नहीं, बल्कि सर्वाइकल कैंसर का उन्मूलन, जो अत्यधिक शारीरिक पीड़ा, भावनात्मक संघर्ष और आर्थिक कठिनाइयों का सबब है। भारत में महिलाओं में यह में दूसरा सबसे आम कैंसर है। हर साल इसके लगभग एक लाख नए मामले सामने आते हैं और इनमें से करीब आधे मामलों में मौत हो जाती है, जो दुनिया भर के कैंसर के बोझ का लगभग एक-चौथाई है। सर्वाइकल कैंसर में जीवन के खोए हुए वर्ष, अन्य कैंसरों की तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि पीड़ित महिलाएँ अपेक्षाकृत कम उम्र की होती हैं और परिवार व समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती हैं। कैंसर विशेषज्ञ के रूप में, मैंने उनकी तकलीफों को करीब से देखा है.. ऐसी महिलाएँ जिनमें चौथी स्टेज में इस रोग का पता चला, उनमें यूरिनरी फिस्टुला विकसित हो चुका था और कंसल्टिंग रूम में उनके दाखिल होने से पहले ही बदबू आने लगती थी; ऐसी महिलाएँ जो रजोनिवृत्ति के बाद होने वाले रक्तस्राव का जिक्र करने में तब तक हिचकिचाती रहीं, जब तक कि बहू ने उनकी साड़ी पर दाग नहीं देख लिया; ऐसी महिलाएँ जो अत्यधिक सायटिक और कमर दर्द, मूत्रवाहिनी या यूरेटर में रुकावट और गुर्दे फेल होने जैसी स्थितियों से जूझ रही थीं... फिर कुछ अपेक्षाकृत भाग्यशाली महिलाएँ भी थीं, जिन्हें शुरूआती अवस्था ही इस रोग से ग्रसित होने के बारे में पता चल गया और जब यह बीमारी ठीक हो सकती थी, लेकिन सिर्फ. रेडिकल सर्जरी या कीमो- और रेडिएशन थेरेपी से... ऐसे में गहन या एग्रेसिव सर्जरी का शरीर पर असर हुआ, लंबे समय तक चले रेडिएशन उपचार के कारण देखभाल करने वालों को पढ़ाई या काम से वंचित रहना पड़ा, और महंगी कीमो व इम्यूनोथेरेपी हुई... इसके अलावा, हमारे हरसंभव प्रयासों के बावजूद कुछ मामलों में कैंसर दोबारा लौट आया, जिसके लिए और भी जटिल प्रक्रियाओं, जैसे एक्सेंटरेशन सर्जरी और स्टोमा आदि की आवश्यकता पड़ी। हाँ, हम इलाज कर सकते थे, लक्षणों में राहत दे सकते थे, यहां तक कि हार्मोन रिप्लेसमेंट और अन्य सहायक देखभाल भी दे सकते थे, लेकिन इसकी शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक कीमत चुकानी होती।

और भी दुखद बात यह थी कि इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती थी। 1940 के दशक से ही पश्चिमी देशों में नियमित पैप स्मीयर जांच के माध्यम से द्वितीयक रोकथाम की व्यवस्था की गई थी, जिससे न केवल कैंसर का पता लगाया जा सकता था, बल्कि रोग की प्रारंभिक अवस्थाओं का भी पता लगाया जा सकता था। सर्वाइकल कैंसर की नेचुरल हिस्ट्री को एक सदी से अधिक समय से अच्छी तरह से दर्ज किया गया है। इसमें 10-15 वर्षों का लंबा प्रीकैंसरस चरण होता है, जिसे सर्वाइकल इंट्राअपिथीलियल नियोप्लासिया (सीआईएन) कहा जाता है, गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स को ब्रश करके स्लाइड पर इकट्ठा की गई कोशिकाओं की माइक्रोस्कोप से जांच करके जिसका पता लगाया जा सकता है। इस अवस्था में इस रोग का उपचार सरल डे-केयर प्रक्रियाओं के जरिए आसानी से किया जा सकता है, जिनमें गर्भाशय निकालने की आवश्यकता नहीं होती। भारत और अन्य निम्न-मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में हमारे पास इतनी बुनियादी सुविधाएँ और प्रशिक्षित जनशक्ति नहीं थी कि 30 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं की जीवन में एक बार भी जांच की जा सके, जबकि हर 3 साल के अंतराल पर यह जांच कराने की सलाह दी गई थी। यहाँ तक कि अच्छे तृतीयक केंद्रों में भी प्रयोगशालाएँ प्रतिदिन सीमित संख्या में ही महिलाओं की जांच कर पाती थीं। देशभर में स्त्रीरोग विशेषज्ञों और पैथोलॉजिस्ट द्वारा नियमित रूप से आउटरीच कैंप आयोजित किए जाते थे, ताकि वंचितों की मदद की जा सके, लेकिन ये प्रयास समुद्र में एक बूंद के समान थे। यहाँ तक कि आज भी, विजुअल इंस्पेक्शन (वीआईए) के माध्यम से राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कार्यक्रम होने के बावजूद, स्क्रीनिंग कवरेज 5% से अधिक नहीं है, और जिन महिलाओं का टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है, उन्हें अस्पताल लाकर रोग की पुष्टि के लिए बायोप्सी और उपचार कराना भी बेहद कठिन होता है।

सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक रोकथाम के लिए एचपीवी टीकाकरण ने 2006 में एक उम्मीद भरे सुपरहीरो की तरह इस परिदृश्य में प्रवेश किया। शुरूआत में यह तीन खुराक वाला टीका था, लेकिन लगातार शोध से यह साबित हुआ कि इसे दो खुराक तक घटाया जा सकता है, और आगे चलकर यह भी पाया गया कि केवल एक खुराक ही 85-90% कैंसर से सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त है। एक साधारण सा इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन इतनी बड़ी तकलीफ से बचा सकता है?! यह वास्तव में बेहद उत्साहजनक संभावना थी। रोकथाम के लिए टीकाकरण में सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। अब तक 500 मिलियन से अधिक खुराकें दुनिया भर में और लगभग 4 मिलियन खुराकें भारत में दी जा चुकी हैं। व्यवस्थित परीक्षणों और पोस्ट-मार्केटिंग सर्विलांस से प्राप्त समेकित आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि टीका लगवाने वाली महिलाओं में सामान्य आबादी की तुलना में प्रतिकूल प्रभावों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उनमें क्षणिक हल्की प्रतिक्रियाएँ देखी गई हैं, जो सभी टीकों में सामान्य होती हैं। इन टीकों का प्रजनन क्षमता, जन्मदर, जन्मजात विकृतियों या मासिक धर्म के पैटर्न पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया है। एचपीवी टीकों की प्रभावशीलता बहुत अच्छी है, क्योंकि ये टीके उनमें शामिल वायरस के प्रकारों से लगभग पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहली पीढ़ी के टीके एचपीवी के दो सबसे खतरनाक प्रकारों – एचपीवी 16 और 18–के खिलाफ बनाए गए थे, जो वैश्विक स्तर पर सर्वाइकल कैंसर के 70% और भारत में लगभग 85% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों, जिन्होंने 2007-08 में इस टीके के शुरू होने के तुरंत बाद ही एचपीवी टीकाकरण लागू कर दिया था, वहाँ प्रीकैंसर तथा कैंसर के मामलों में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा और अमेरिका जैसे अन्य देशों से भी इसी तरह के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

डब्ल्यूएचओ की सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन पहल का लक्ष्य सर्वाइकल कैंसर को एक दुर्लभ कैंसर बनाना है, जिसके होने की दर प्रति 1 लाख में केवल 4 मामलों तक सीमित हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2030 तक : 15 वर्ष की आयु से पहले 90% लड़कियों का एचपीवी टीकाकरण, 35 और 45 वर्ष की आयु में 70% महिलाओं की एचपीवी परीक्षण द्वारा स्क्रीनिंग, और जिन महिलाओं में रोग के लक्षण पाए जाएं, उनमें से 90% का उपचार - जैसे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को हासिल करना आवश्यक है। वैश्विक घोषणा के शुरू होने के बाद से हम आधे से अधिक रास्ता पार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इन लक्ष्यों की प्राप्ति से काफी दूर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ऑफ इंडिया (एफओजीएसआई) और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) जैसे संगठनों के प्रतिनिधित्व वाला चिकित्सा समुदाय लंबे अरसे से एचपीवी टीकाकरण को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। आखिरकार, अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है– माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान को देशव्यापी स्तर पर लॉन्च किया जाना- महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों को महत्व दिलाने की दिशा में सर्वोच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता का संकेत है, जिसकी वे हकदार हैं। पहुँच, किफायत और उपलब्धता जैसी प्रमुख चिंताओं का सरकार ने पूरी तरह समाधान कर दिया है। अब सभी अभिभावकों को इस सुनहरे अवसर के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि उनकी 14 साल की बेटियाँ नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क टीकाकरण का लाभ उठा सकें। हमारी बेटियों के लिए एक साधारण सा टीका, सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन और विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा।

आज का राशिफल

मेषः आज व्यापारिक मामलों में सतर्कता बरतना जरूरी है। पुराने विवाद फिर से सामने आ सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। मनचाहे परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है। *(सिटी दर्पण)*

वृषभः नया बिजनेस शुरू करने के लिए आप कर्ज लेने पर विचार कर सकते हैं। नौकरी बदलने का विचार भी मन में आ सकता है। प्रभावशाली लोगों से संपर्क लाभदायक साबित होगा। आय के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी के साथ निर्णय लें। *(सिटी दर्पण)*

मिथुनः विदेश यात्रा या उससे जुड़े अवसर मिलने के संकेत हैं। भाइयों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें। गलत संगति से दूरी बनाना आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यस्थल पर अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संयम और आत्मविश्वास बनाए रखें। *(सिटी दर्पण)*

कर्कः आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है। युवाओं को बड़ी कंपनियों से नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। व्यापार में नई रणनीति अपनाने से लाभ होगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रिश्तों में भी मजबूती आएगी। *(सिटी दर्पण)*

सिंहः प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाई में पूरी एकाग्रता रखनी होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से पीठ या कंधे में दर्द परेशान कर सकता है। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। नशे से दूरी बनाकर रखें। *(सिटी दर्पण)*

कन्याः जिस कार्य को आप मुश्किल समझ रहे थे, उसमें आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति आपको सफलता दिलाएगी। हालांकि भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। आसपास के लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। मित्रों की मदद करने का अवसर मिलेगा और प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी। *(सिटी दर्पण)*

तुलाः रुके हुए काम आज पूरे होने के योग हैं। बड़े फैसले लेने और महत्वपूर्ण सौदे करने के लिए समय अनुकूल है। पिता या किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन मिलेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और कार्यक्षेत्र में अधिकार बढ़ सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिकः आज आप अपने लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे। व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं और साझेदारों के साथ संबंध मजबूत होंगे। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, जिससे समाज में सम्मान मिलेगा। परिवार के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है। *(सिटी दर्पण)*

धनुः करियर को लेकर मन में असमंजस और चिंता रह सकती है। पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर आंख मूंदकर विश्वास न करें। आय-व्यय का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कानूनी मामलों में लापरवाही से बचें। *(सिटी दर्पण)*

मकरः जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ होने की संभावना है। नई चीजों पर खर्च बढ़ सकता है। बेरोजगारों को नौकरी मिलने के संकेत हैं। *(सिटी दर्पण)*

कुंभः अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। प्रेम जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी। अपने विचार दूसरों पर थोपने से बचें। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। अच्छे लोगों की संगत से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। *(सिटी दर्पण)*

मीनः प्रेम संबंधों में गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। बोलने से पहले सोच-समझकर शब्दों का चयन करें। मौसम बदलने के कारण स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑनलाइन नए दोस्त बन सकते हैं। कमीशन या डीलिंग से जुड़े कार्यों में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। *(सिटी दर्पण)*

वैश्विक संकट और ऊर्जा संरक्षण

योगेश कुमार गोयल
(हि.स)

आज समूचा विश्व भू-राजनीतिक तनाव के दौर से गुजर रहा है। ईरान, अमेरिका तथा इजराइल के बीच के टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। इसलिए ऊर्जा केवल विकास का साधन नहीं बल्कि अस्तित्व का प्रश्न बन चुकी है। तेल और गैस के दामों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और ऊर्जा स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या आधुनिक सभ्यता ने अपनी बुनियाद अत्यधिक अस्थिर संसाधनों पर खड़ी कर दी है। इस परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि मानवता की सुरक्षा का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय बनकर उभर रहा है। ऊर्जा आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग है, चाहे वह उद्योगों की मशीनें हों, परिवहन के साधन हों, डिजिटल अर्थव्यवस्था हो या घरेलू जीवन की सुविधाएं किंतु विडंबना यह है कि जिस ऊर्जा पर हमारी प्रगति आधारित है, वही अब संकट का कारण बनती जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र की 'एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024' के अनुसार आने वाले दशक में वैश्विक ऊर्जा मांग में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है जबकि जीवाश्म ईंधनों के भंडार तेजी से सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे में यदि ऊर्जा संरक्षण और दक्षता को प्राथमिकता नहीं दी गई तो भविष्य में ऊर्जा संकट केवल आर्थिक चुनौती नहीं रहेगा बल्कि सामाजिक अस्थिरता और वैश्विक संघर्षों का कारण भी बन सकता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य इस खतरे को और स्पष्ट करता है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव ने तेल आपूर्ति पर अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हो रही हैं। भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। दरअसल भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है। ऐसे में वैश्विक संकट का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम नागरिक के जीवन पर पड़ता है। पैट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि केवल परिवहन लागत को नहीं बढ़ाती बल्कि खाद्य पदार्थों से लेकर निर्माण सामग्री तक हर क्षेत्र में महंगाई को जन्म देती है। इस परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण आधार बन जाता है।

भारत तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और यहां ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की 'इंडिया एनर्जी आउटलुक 2024' रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊर्जा उपभोक्ता अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसे में यदि ऊर्जा खपत को संतुलित नहीं किया गया तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाएगा। यही कारण है कि भारत ने ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को अपनी नीति का केंद्रीय तत्व बनाया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और 'उजाला' जैसे कार्यक्रमों ने यह साबित किया है कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्बों का वितरण और उससे हुई 48 बिलियन यूनिट बिजली की बचत इस बात का प्रमाण है कि यदि नीति और जनभागीदारी साथ आएं तो ऊर्जा संरक्षण एक जनांदोलन बन सकता है।

ऊर्जा संरक्षण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह किसी नई तकनीक या बड़े निवेश पर निर्भर नहीं है बल्कि यह हमारे दैनिक व्यवहार में छोटे-छोटे बदलावों से ही संभव है। उदाहरण के लिए, अनावश्यक रूप से जलती लाइटों को बंद करना, ऊर्जा-कुशल उपकरणों का उपयोग करना, एयर कंडीशनर का सीमित प्रयोग, सार्वजनिक परिवहन को अपनाना और सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना, ये सभी कदम न केवल ऊर्जा बचाते हैं बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। यदि भारत का प्रत्येक परिवार प्रतिदिन केवल एक यूनिट बिजली की बचत करे तो यह देश के लिए ऊर्जा क्रांति के समान होगा। ऊर्जा संरक्षण का संबंध केवल बिजली तक सीमित नहीं है बल्कि यह जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा उत्पादन में जल का व्यापक उपयोग होता है और जल की बरबादी सीधे ऊर्जा की बबार्दी में बदल जाती है। इसी प्रकार, ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, जो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है। आज जब दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, तब ऊर्जा संरक्षण इस दिशा में सबसे प्रभावी हथियार साबित हो सकता है।

अक्षय ऊर्जा इस संकट का दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करती है लेकिन इसकी सफलता भी ऊर्जा संरक्षण पर ही निर्भर करती है। सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे स्रोतों का विस्तार तभी प्रभावी होगा, जब ऊर्जा की कुल मांग को नियंत्रित किया जाए। भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है बल्कि वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और स्मार्ट ग्रिड जैसी तकनीकें इस दिशा में नई संभावनाएं खोल रही हैं लेकिन इन सबका मूल आधार ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग ही है। शहरीकरण के बढ़ते दबाव ने भी ऊर्जा खपत को तेजी से बढ़ाया है। महानगरों में ऊंची इमारतें, एयर कंडीशनिंग सिस्टम और बढ़ती वाहन संख्या ऊर्जा की मांग को कई गुना बढ़ा देती है। ऐसे में हरित भवन निर्माण, सौर पैनलों का उपयोग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना आवश्यक हो जाता है। यदि भवन निर्माण में ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता दी जाए तो बिजली की खपत में 30 से 40 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है। यह न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

ऊर्जा संरक्षण का एक महत्वपूर्ण आयाम औद्योगिक क्षेत्र भी है। उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने से उत्पादन लागत में कमी आती है और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऊर्जा संरक्षण को केवल सरकारी नीति या अभियान के रूप में न देखा जाए बल्कि इसे एक सामाजिक संस्कृति के रूप में विकसित किया जाए। विद्यालयों में ऊर्जा शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए, मीडिया के माध्यम से जनजागरुकता बढ़ाई जाए और प्रत्येक नागरिक को यह समझाया जाए कि ऊर्जा की बचत केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य है। जब तक ऊर्जा संरक्षण हमारी आदत नहीं बनेगा, तब तक किसी भी नीति या तकनीक का पूर्ण लाभ नहीं मिल सकेगा।

वैश्विक ऊर्जा संकट के इस दौर में भारत के पास एक अवसर भी है, एक ऐसे मॉडल के रूप में उभरने का, जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित कर सके। यदि भारत ऊर्जा संरक्षण, अक्षय ऊर्जा और तकनीकी नवाचार के समन्वय से आगे बढ़ता है तो वह न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है बल्कि विश्व के लिए एक प्रेरणा भी बन सकता है। यह समझना आवश्यक है कि ऊर्जा का संकट केवल संसाधनों का संकट नहीं है बल्कि यह हमारी सोच और व्यवहार का संकट भी है। यदि हम ऊर्जा को अनमोल संसाधन मानकर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना सीख लें तो न केवल वर्तमान संकट से उबर सकते हैं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध दुनिया भी सुनिश्चित कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण कोई जटिल विज्ञान नहीं बल्कि एक सरल जीवनशैली है और यही जीवनशैली आज धरती को बचाने की सबसे प्रभावी चाबी बन चुकी है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

भगवंत मान सरकार द्वारा व्यापारियों की 1,386 शिकायतों की समीक्षा, पी.एस.टी.सी. के माध्यम से समयबद्ध समाधान पर जोर: हरपाल सिंह चीमा

व्यापारियों के साथ संरचित संवाद सुनिश्चित करने के लिए पंजाब भर में 256 पी.एस.टी.सी. बैठकें आयोजित की गई

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- भगवंत मान सरकार व्यापारियों के लिए पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत कर रही है: हरपाल सिंह चीमा
- पंजाब सरकार द्वारा एस.ओ.पी. का सख्त पालन अनिवार्य, व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए जवाबदेही तय की गई: हरपाल सिंह चीमा

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां पंजाब राज्य व्यापारी आयोग (पी.एस.टी.सी.) की राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भगवंत मान सरकार एक सख्त, जवाबदेह और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से व्यापारियों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान प्रदान करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है।

पंजाब भर में आयोजित 256 बैठकों की प्रगति और 1,386 शिकायतों की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने व्यापारी समुदाय के साथ संरचित संवाद को संस्थागत रूप दिया है, एस.ओ.पी. के सख्त पालन को लागू किया है और हर स्तर पर स्पष्ट प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करते हुए जमीनी स्तर पर समस्याओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए तीन-स्तरीय पी.एस.टी.सी. ढांचे को सक्रिय किया है।

बैठक का मुख्य केंद्र शिकायतों की मास्टर सूची की गहन समीक्षा करना था, जो लंबित मामलों के समाधान और व्यापारिक समुदाय द्वारा उठाई गई नई चिंताओं को सक्रिय रूप से दर्ज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पी.एस.टी.सी. के जमीनी स्तर के प्रभाव को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, ‘राज्य भर में पहले ही 256 बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं। इस ढांचे का मुख्य उद्देश्य राज्य प्रशासन और व्यापारी समुदाय के बीच एक नियमित, संरचित और पारस्परिक रूप से लाभकारी संवाद को सुगम बनाना है। इस औपचारिक प्रणाली को मजबूत करके, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का उद्देश्य व्यापारियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक अत्यंत पारदर्शी और जवाबदेह मंच प्रदान करना है।

इसके अलावा, बैठक में इन मुद्दों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, दस्तावेजीकरण और समाधान के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर स्पष्ट प्रशासनिक जिम्मेदारियां तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि सार्वजनिक जवाबदेही के लिए बैठकों के सभी रिकॉर्ड, तस्वीरें और शिकायतों के समाधान को तुरंत सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

बैठक के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पी.एस.टी.सी. के मजबूत तीन-स्तरीय ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। बैठक में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो पी.एस.टी.सी. के अध्यक्ष भी हैं, के साथ आबकारी एवं कर आयुक्त जतिंदर जोरवाल भी उपस्थित थे।

चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, नगर निगम आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) शामिल हुए। उनके साथ पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के चेयरपर्सन और सदस्य, तथा जिला और विधानसभा क्षेत्र व्यापारी आयोगों के चेयरमैन भी उपस्थित थे, जिन्होंने सरकार के निदेशों को जमीनी स्तर पर तुरंत लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने स्थानीय डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों से सीधे भाग लिया।

बरिंदर कुमार गोयल ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लहरागागा की नई इमारत का शिलान्यास किया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/लहरागागा

पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां), लहरागागा की 20.16 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली नई इमारत का शिलान्यास कर इस महत्वपूर्ण परियोजना की शुरूआत की।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नई इमारत के तैयार होने से छात्राओं को सुरक्षित और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण मिलेगा, जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होगा।

उन्होंने बताया कि पहले इस स्कूल में स्थान की काफी कमी थी और मौजूदा भवन के कई हिस्सों को असुरक्षित घोषित किया जा चुका था, जिससे छात्राओं और स्टाफ को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब नई इमारत को आधुनिक डिजाइन के अनुसार तैयार किया जा रहा है, जिसमें बड़े कक्ष, बेहतर वेंटिलेशन और रोशनी, भूकंपरोधी ढांचा तथा छात्राओं के अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना लगभग 7-8 महीनों में पूरी कर ली जाएगी और क्षेत्र को एक मॉडल स्कूल मिलेगा।

मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि नई इमारत के तैयार होने के बाद स्कूल में मेडिकल, नॉन-मेडिकल और कॉमर्स धाराओं की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इससे क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अपने क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी।

उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना के तहत विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, आधुनिक पुस्तकालय, स्मार्ट कक्षाएं, खेल सुविधाएं और स्वच्छ सैनिटेशन व्यवस्था विकसित की जाएगी। छात्राओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी सहित अन्य आवश्यक प्रबंध भी किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि हर वर्ग के बच्चों को समान और उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों का बदलता स्वरूप इस बात का प्रमाण है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी और प्रभावी निर्णय ले रही है।

इस मौके पर नगर परिषद लहरागागा की प्रधान और इस स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल श्रीमती कांता गोयल, एसडीएम राकेश प्रकाश सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी, स्कूल स्टाफ, छात्राएं और क्षेत्र के प्रमुख लोग उपस्थित थे।

आईपीएल 2026 से पूर्व पंजाब किंग्स के सीईओ एवं सीएफओ ने पंजाब के राज्यपाल से भेंट कर आशीर्वाद लिया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब किंग्स के एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सतीश मेनन एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री एल. सी. गुप्ता शामिल थे, ने आज पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया से पंजाब लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की।

प्रतिनिधिमंडल ने आगामी आईपीएल 2026 सीजन से पूर्व राज्यपाल से भेंट कर आशीर्वाद एवं शुभकामनाएँ प्राप्त कीं।

इस अवसर पर पंजाब किंग्स के प्रतिनिधियों ने टीम की तैयारियों, दृष्टिकोण तथा क्रिकेट में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने क्षेत्र में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता तथा पंजाब के युवाओं को प्रेरित करने में टीम की भूमिका पर भी चर्चा की। राज्यपाल ने टीम को आगामी आईपीएल सीजन के लिए अपनी शुभकामनाएँ देते हुए सफल एवं उत्साहपूर्ण प्रदर्शन की कामना की। उन्होंने राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा उभरते क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने में पंजाब किंग्स के योगदान की सराहना की।

ट्राइडेंट ग्रुप ने बुधनी में 5.40 मेगावाट का नया रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट किया शुरू, कुल क्षमता 57.32 मेगावाट पहुंची

चंडीगढ़। ट्राइडेंट ग्रुप, जो कि टेक्सटाइल, पेपर, केमिकल और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय एक प्रमुख समूह है, ने मध्य प्रदेश के अपने बुधनी स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 5.40 मेगावाट क्षमता का नया अतिरिक्त रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। इस विस्तार के साथ ही प्लांट की कुल सोलर क्षमता बढ़कर 57.32 मेगावाट हो गई है। कंपनी ने एक बयान में बताया कि इससे पहले इस यूनिट में 51.92 मेगावाट सोलर क्षमता स्थापित थी, जिसका 100 प्रतिशत उपयोग किया जा रहा था। नया प्रोजेक्ट तय समयसीमा के अनुसार 27 मार्च 2026 को पूरा किया गया। इस परियोजना पर करीब 10 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। ग्रुप के मुताबिक, यह कदम सतत विकास (सस्टेनेबल ग्रोथ) को बढ़ावा देने और बड़े स्तर पर ऑपरेशनल दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। इसके साथ ही बुधनी प्लांट सेंट्रल इंडिया में ट्राइडेंट की रिन्यूएबल एनर्जी पहलों का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। कंपनी का कहना है कि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन से ऊर्जा दक्षता में सुधार होगा और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी। ट्राइडेंट ग्रुप लगातार नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रहा है, जो उसके ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ऊर्जा दक्षता और जिम्मेदार विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले एक दशक में ग्रुप ने अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में स्वच्छ, हरित और किफायती ऊर्जा समाधान को बढ़ावा दिया है। ग्रुप सौर ऊर्जा के उपयोग के साथ-साथ जल पुनः उपयोग (रीयूज़) को भी अपनाए हुए है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट में उल्लेखनीय कमी आई है और कंपनी के पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) लक्ष्यों को मजबूती मिली है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे अनुकूल नीतियों और बढ़ते सस्टेनेबिलिटी फोकस का समर्थन मिल रहा है।

डॉ. रवजोत सिंह ने जेल मंत्री का पदभार संभाला; पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल और मुख्यमंत्री मान का नई जिम्मेदारी के लिए किया धन्यवाद

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- कहा, जेल विभाग को और सुधारने, कैदियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और सुधारात्मक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए उठाए जाएंगे कदम

पंजाब सरकार में नए जेल मंत्री के रूप में डॉ. रवजोत सिंह ने आज पंजाब सिविल सचिवालय में अपने पद का कार्यभार संभाल लिया। इसके अलावा वे एनआरआई और संसदीय मामलों जैसे विभागों की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं।

कार्यभार संभालने के बाद डॉ. रवजोत सिंह ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें यह जिम्मेदारी देकर जो विश्वास जताया गया है, उस पर वे पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे।

इस अवसर पर उन्होंने जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विभाग के चल रहे कार्यों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

उन्होंने कहा कि जेल विभाग को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा तथा कैदियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और सुधारात्मक प्रणाली को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जेलों को केवल सजा के केंद्र नहीं, बल्कि सुधार के केंद्र के रूप में विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

बैठक के दौरान जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक प्रस्तुति के माध्यम से विभाग के चल रहे प्रोजेक्ट्स, पहल और चुनौतियों के बारे में नए मंत्री को विस्तृत जानकारी दी गई। नए जेल मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने अधिकारियों को विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकारों का पालन सुनिश्चित करने तथा जेल प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए।

इस मौके पर जेल विभाग की प्रमुख सचिव भावना गर्ग, सचिव मोहम्मद तैयब और एडीजीपी जेल अरुणपाल सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

8 स्थानों पर एक साथ हुई छापेमारी ने तंबाकू व्यापार में टैक्स चोरी के नेटवर्क का किया पदार्फाश: चीमा

भगवंत सिंह मान सरकार की तंबाकू टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई में 1.5 करोड़ रुपये का बिना बिल का सामान बरामद; वसूली जारी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- टैक्स चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, भगवंत मान सरकार ने अवैध तंबाकू व्यापार पर कार्रवाई की तेज: हरपाल सिंह चीमा
- गैर-रजिस्टर्ड कारोबार और छिपा हुआ स्टॉक बरामद, भगवंत मान सरकार ने टैक्स चोरों पर कसा शिकंजा: हरपाल सिंह चीमा

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां बताया कि कर विभाग ने तंबाकू टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने के लिए पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर समन्वित प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) अभियान शुरू किया है, जिसके तहत लगभग 1.5 करोड़ रुपये के बिना हिसाब-किताब (अनअकाउंटेड) सामान का पता लगाया गया है।

कार्रवाई के विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया, सिगरेट, बीड़ी और अन्य संबंधित तंबाकू उत्पादों पर हाल ही में टैक्स दरों में वृद्धि के बाद विभाग को इस क्षेत्र में टैक्स चोरी की गतिविधियों में बढ़ोतरी की सूचना मिली थी। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर स्थित चार स्टेट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंटिव यूनिट्स की टीमों को सक्रिय किया गया। इन टीमों ने आठ अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी की, जिनमें पांच रजिस्टर्ड कारोबारों और तीन बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे व्यवसायों की जांच की गई।

इनफोर्समेंट अभियान की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, लुधियाना और अमृतसर में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां सामने आईं, जहां प्रवर्तन टीमों ने गुप्त स्टोरेज स्थानों और बिना हिसाब वाले स्टॉक की पहचान की। मुख्य दुकानों और उनसे जुड़े गोदामों की गहन जांच के दौरान भारी मात्रा में सामान बिना वैध बिल (इनवॉइस) के संग्रहीत और बेचा जा रहा था।

उन्होंने आगे बताया कि जब्त किए गए स्टॉक में भारत में निर्मित सिगरेट के लगभग 1.32 लाख पैकेट, बीड़ी के 18,472 पैकेट, जर्दा के 302 पैकेट, विदेशी सिगरेट के 13 पैकेट और 95 डिब्बे, विदेशी निर्मित हुक्का सामग्री के 148 पीस, 13,000 लाइटर और कूललिप के 18 पैकेट शामिल हैं। वित्तीय आकलन के संबंध में मंत्री ने कहा, जब्त सामान पर लागू कानूनों के तहत जुमार्ने के अलावा 50 लाख रुपये से अधिक की टैक्स देनदारी सख्ती से वसूली जाएगी। अब तक 12 लाख रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है और आगे की वसूली की कार्रवाई तेजी से जारी है।

टैक्स चोरी के खिलाफ सरकार की ह्यजीरो टॉलरेंसह्न नीति को दोहराते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि टैक्स अनुपालन सुनिश्चित करने और राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए ऐसे समन्वित प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने व्यापारियों को सख्त सलाह दी कि वे उचित दस्तावेज बनाए रखें और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नियमों का पूरी तरह पालन करें।

संक्षिप्त-समाचार

ब्यास और हजरत निजामुद्दीन तथा ब्यास और सहारनपुर के बीच स्पैशल ट्रेन सेवाओं का संचालन

जैतो। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक परमदीप सिंह सैनी ने शुक्रवार को कहा कि रेलवे द्वारा ब्यास में राधा स्वामी सत्संग के भक्तों की सुविधा हेतु मेल एक्सप्रेस स्पैशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जिसका विवरण इस प्रकार है। ट्रेन 04451/04452 हजरत निजामुद्दीन-ब्यास-हजरत निजामुद्दीन मेल एक्सप्रेस स्पैशल ट्रेन।स्पैशल ट्रेन 04451 हजरत निजामुद्दीन से ब्यास के लिए 23.04.2026 तथा 07.05.2026 (02 ट्रिप) को चलेगी। यह स्पैशल ट्रेन 04451 हजरत निजामुद्दीन से शाम 19:40 बजे प्रस्थान करके 8 घंटे और 25 मिनट बाद सुबह 04:05 बजे ब्यास पहुँचेगी। वापसी दिशा में स्पैशल ट्रेन 04452 ब्यास से हजरत निजामुद्दीन के लिए 26.04.2026 तथा 10.05.2026 (02 ट्रिप) को चलेगी। यह स्पैशल ट्रेन 04452 ब्यास से रात्रि 20:35 बजे प्रस्थान करके 7 घंटे और 25 मिनट बाद सुबह 04:00 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुँचेगी।मार्ग में यह स्पैशल ट्रेन नई दिल्ली, सब्जी मंडी, अम्बाला छावनी, लुधियाना और जालंधर सिटी रेलवे स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी। 04565/04566 सहारनपुर-ब्यास-सहारनपुर मेल एक्सप्रेस स्पैशल ट्रेन।स्पैशल ट्रेन 04565 सहारनपुर से ब्यास के लिए 24.04.2026, 01.05.2025 तथा 08.05.2026 (03 ट्रिप) को चलेगी। यह स्पैशल ट्रेन 04565 सहारनपुर से रात्रि 20:50 बजे प्रस्थान करके 6 घंटे 25 मिनट बाद सुबह 02:15 बजे ब्यास पहुँचेगी। वापसी दिशा में, स्पेशल ट्रेन 04566 ब्यास से सहारनपुर के लिए 26.04.2026, 03.05.2026 तथा 10.05.2026 (03 ट्रिप) को चलेगी। यह स्पैशल ट्रेन 04566 ब्यास से शाम 15:00 बजे प्रस्थान करके 6 घंटे 10 मिनट बाद रात्रि 21:10 बजे सहारनपुर पहुँचेगी।मार्ग में यह स्पैशल ट्रेन यमुनानगर जगाधरी, जगाधरी वर्कशॉप, अम्बाला छावनी, लुधियाना और जालंधर सिटी रेलवे स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी।

एस.सी. आयोग द्वारा दलित छात्र को प्रवेश न देने के मामले में राजिंदर कॉलेज बठिंडा की प्रिंसिपल तलब

चंडीगढ़। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने एक अनुसूचित जाति से संबंधित छात्र को राजिंदरा कॉलेज, बठिंडा में प्रवेश न दिए जाने के मामले का संज्ञान लेते हुए कॉलेज की प्रिंसिपल को तलब किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला एक अखबार में प्रकाशित खबर के माध्यम से आयोग के ध्यान में आया। इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने राजिंदरा कॉलेज, बठिंडा की प्रिंसिपल को 1 अप्रैल 2026 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

ट्राईसिटी बनेगा फैशन का हॉटस्पॉट, नॉर्थ इंडिया आइकॉनिक सीजन-2 29 मार्च को

जीरकपुर। ट्राईसिटी में ग्लैमर और फैशन का बड़ा धमाका होने जा रहा है। रॉयल पार्क रिजॉर्ट, जीरकपुर में 29 मार्च को ह्यनॉर्थ इंडिया आइकॉनिक सीजन-2ह्न का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें देशभर के उभरते और प्रोफेशनल मॉडल्स अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरेंगे। इस मेगा इवेंट का आयोजन एसजी प्रोडक्शन व प्रीति अरोड़ा एंटरटेनमेंट द्वारा किया जा रहा है, कार्यक्रम में मॉडलिंग वर्कशॉप, ग्रैंड फैशन शो, प्रोफेशनल फोटोशूट, नेटवर्किंग सेशन और मॉडलिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतिभागियों को इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से सीखने, अपने हुनर को निखारने और बड़े प्लेटफॉर्म पर खुद को साबित करने का शानदार मौका मिलेगा। आयोजकों के अनुसार यह इवेंट नई प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के साथ-साथ उन्हें प्रोफेशनल ग्रूमिंग और बेहतरीन एक्सपोजर भी प्रदान करेगा। ग्लैमर, टैलेंट और अवसर-तीनों का शानदार संगम इस इवेंट में देखने को मिलेगा, जो ट्राईसिटी को फैशन इंडस्ट्री का नया हॉटस्पॉट बनाने की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा।

किन्नर मंदिर में रामनवमी पर 151 कन्याओं का कंजक पूजन

चंडीगढ़। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर रामनवमी का पर्व जय माता किन्नर मंदिर, बापूधाम सेक्टर 26 में बड़ी ही श्रद्धाभाव और भक्तिमय रूप से मनाया गया। परमपूज्यपाद जय माता मंदिर पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामण्डलेश्वर माँ कमलीनन्द गिरी जी- अंतरराष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा व जूना अखाड़ा की देखरेख में मंदिर परिसर में कंजक पूजन और 108 कलश के जल से माता का अभिषेक किया गया। परमपूज्यपाद जय माता मंदिर पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामण्डलेश्वर माँ कमलीनन्द गिरी जी महाराज ने बताया कि मंदिर में नवरात्र का पर्व बड़े ही श्रद्धाभाव और भक्तिभाव से मनाया गया। मंदिर में नौ दिन माता के नौ स्वरूपों की मंदिर के 09 पुजारियों द्वारा श्रद्धाभाव से पूजा अर्चना की गई। उन्होंने बताया कि नवरात्र के दौरान रामनवमी अवसर पर 151 कन्याओं एवम लगभग 50 बालकों का पूजन किया गया। इसके अलावा सभी को आशीर्वाद भी दिया गया है। नौ दिन माता की पूजा अर्चना की गई है। आज रामनवमी अवसर पर हवन यज्ञ, माता की आरती, 09 पंडित पूजन सहित कंजक पूजन किया गया।

इमैजिन ट्रेजर ने नेक्सस एलांते मॉल चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा एप्पल प्रीमियम पार्टनर स्टोर लॉन्च किया

चंडीगढ़। इमैजिन ट्रेजर, जो भारत के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा ग्राहक-केंद्रित एप्पल पार्टनर्स में से एक है, ने आज चंडीगढ़ के नेक्सस एलांते मॉल में उत्तर भारत के सबसे बड़े एप्पल प्रीमियम पार्टनर स्टोर और एक खास एप्पल ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया। इस शानदार उद्घाटन समारोह में पंजाब पुलिस की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के एडीजीपी श्री ए.के. पांडे, मशहूर युट्यूबर गौरव चौधरी (टेक्निकल गुरु) ट्रेजर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ श्री शौर्य सेठ और ट्रेजर परिवार के वरिष्ठ नेतृत्व सदस्यों ने शिरकत की। इस मौके पर विशेष मेहमान श्री ए.के. पांडे ने इमैजिन एप्पल स्टोर के उद्घाटन पर बधाई देते हुए कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि ऐसी पहलें हमारे युवाओं और उद्यमियों की बढ़ती डिजिटल आकांक्षाओं को दर्शाती हैं। आज शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण में टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका निभाती है। इमैजिन स्टोर जैसी प्रीमियम रिटेल और सर्विस डेस्टिनेशन का आना एक डिजिटल रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर समाज बनाने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। मुझे विश्वास है कि यह स्टोर न केवल इनोवेशन का केंद्र बनेगा, बल्कि कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा।

नेपाल के राष्ट्रपति ने बालेन्द्र शाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया

बालेन्द्र शाह की पहली कैबिनेट बैठक 100 दिन 100 एजेंडा प्रस्ताव पारित करेगी

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह शुक्रवार को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय ने उन्हें प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने की जानकारी दी है। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने नेपाल के संविधान की धारा 76 की उपधारा 1 के अनुसार आरएसपी के एकल बहुमत के आधार पर उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।

बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार में कई पुरानी परंपराओं को बदलने की योजना बनाई गई है। इनमें पहली कैबिनेट बैठक से 100 दिन 100 एजेंडा का प्रस्ताव पारित करने की तैयारी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने इस बार संकेत दिया है कि मंत्री शपथ के बाद किए जाने वाले 'पहले निर्णय' की परंपरा को जारी नहीं रखा जाएगा। इसके बजाय, कैबिनेट स्तर पर ही 100 दिनों के भीतर लागू करने के लक्ष्य के साथ '100 निर्णय' लेने की तैयारी की जा रही है। बालेन के करीबी नेता कुमार बेन ने कहा, मंत्री व्यक्तिगत रूप से पहला निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि कैबिनेट ही प्राथमिकताओं के आधार पर 100 फैसले करेगी। इसके बाद संबंधित मंत्रालय अपने अधिकार क्षेत्र में उन निर्णयों को लागू करेंगे—और परिणाम भी वहीं से दिखाई देंगे।

काठमांडू के मेयर से सिंह दरबार तक बालेन्द्र शाह का असाधारण सफर

काठमांडू। नेपाल की समकालीन राजनीति में एक ऐसा नाम उभरा है जिसने पारंपरिक ढांचे को चुनौती देते हुए युवाओं की आकांक्षाओं को नई दिशा दी। वो नाम है– बालेन्द्र शाह (बालेन)। एक रैपर, इंजीनियर। देश के प्रधानमंत्री पद तक का उनका सफर न केवल असामान्य है, बल्कि यह नेपाल की बदलती राजनीतिक संस्कृति का प्रतीक भी बन चुका है। राजनीति में आने से पहले बालेन शाह नेपाल के हिप-हॉप जगत में एक जाना-पहचाना नाम रहे हैं। बालेन का राजनीतिक प्रवेश पारंपरिक दलों से अलग रहा। उन्होंने खुद को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया और राजनीति में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी दक्षता को प्राथमिकता दी। 2022 में काठमांडू महानगरपालिका के मेयर के रूप में उनकी जीत ऐतिहासिक रही। मेयर बनने के बाद उन्होंने कई सख्त और त्वरित फैसले लिए, जैसे- अवैध संरचनाओं पर कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों का संरक्षण, शहरी प्रबंधन में सुधार। इन कदमों ने उन्हें एक्शन-ओरिएंटेड नेता के रूप में स्थापित किया। बालेन शाह को नेपाल में जेन जेड आंदोलन का प्रतीक माना जाता है। सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग और सीधे संवाद की शैली ने उन्हें युवाओं का अपना नेता बना दिया। जहां एक ओर उनके फैसलों की सराहना हुई, वहीं कई कदम विवादों में भी रहे। वह अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई को लेकर आलोचना के केंद्र में रहे। प्रशासनिक प्रक्रिया को दरकिनार करने का आरोप लगा। अभिव्यक्ति और नीति के बीच संतुलन पर सवाल उठे। राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश के बाद बालेन शाह ने आम चुनाव में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को संसद में दो-तिहाई बहुमत मिला–जो नेपाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद बालेन शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।

शपथग्रहण से ठीक पहले बालेन ने रिलीज किया अपना नया रैप

काठमांडू। प्रधानमंत्री पद की आज शपथ लेने जा रहे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह का प्रभाव सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि संगीत क्षेत्र में भी उतना ही प्रभावशाली है। शपथ ग्रहण से एक दिन पहले गुरुवार को सार्वजनिक किए गए उनके चर्चित रैप गीत 'जय महाकाली' ने यू-ट्यूब पर नेपाली गीतों के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस गीत को रिलीज होने के मात्र 24 घंटे के भीतर ही 28 लाख से अधिक बार देखा गया। यह अब तक का सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला नेपाली गीत बन गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड दुर्गेश थापा और सिसन बानियाँ के सहयोग से बने गीत 'जाने भए जाम माया' के नाम था, जिसे 24 घंटे में 16 लाख 36 हजार व्यूज मिले थे। इसी तरह, यह गीत सार्वजनिक होने के केवल 3 घंटे के भीतर ही 10 लाख व्यूज पार कर सबसे तेजी से 10 लाख व्यूज हासिल करने वाला नेपाली गीत भी बन गया है। 'जय महाकाली' का ऑडियो 11 वर्ष पहले ही तैयार हुआ था।

उत्तर कोरिया और बेलारूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का समर्थन किया

किम और लुकाशेंको ने शिखर वार्ता में सहयोग संधि पर किए हस्ताक्षर

फोटो: हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

प्योंगयांग (उत्तर कोरिया)

उत्तर कोरिया और बेलारूस ने यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन किया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गुरुवार को शिखर वार्ता में समर्थन दोहराते हुए दोस्ती व सहयोग पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

द कोरिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी लुकाशेंको ने किम के निमंत्रण पर बुधवार और गुरुवार को उत्तर कोरिया का दो दिवसीय आधिकारिक दौरा किया। शिखर वार्ता के दौरान लुकाशेंको ने कहा कि प्योंगयांग-मिन्स्क संबंधों ने विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर लिया है। इस दौरान किम ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर संप्रभु अधिकारों की रक्षा करने की बेलारूसी नेता की नीति के प्रति एकजुटता व्यक्त की। इस दौरान बेलारूस और उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध का समर्थन किया और इसी आधार पर दोनों देशों ने अपने संबंधों को सहयोग को मजबूत किया है। साथ ही दोनों नेताओं ने उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से कई योजनाओं पर चर्चा की। आपसी चिंता से जुड़े अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बात की।

किम और लुकाशेंको ने मित्रता और सहयोग पर एक संधि के अलावा कूटनीति, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े कई समझौतों पर भी दस्तखत किए। बातचीत के बाद नेताओं ने फोटो खिंचवाए और उपहारों का आदान-प्रदान किया। दौरे के आखिरी चरण में किम ने लुकाशेंको के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया।

दोनों नेताओं ने आइस रिंक पर एक कलात्मक प्रस्तुति भी देखी। गुरुवार को बेलारूस के राष्ट्रपति प्योंगयांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपने निजी जेट से रवाना हो गए। किम उन्हें विदा करने के लिए वहां मौजूद रहे। उत्तर कोरिया और बेलारूस ने औपचारिक रूप से 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 1995 से दोनों संयुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग समिति का संचालन कर रहे हैं।

जयशंकर ने फ्रांस में जी 7 विदेशमंत्रियों से वैश्विक शासन में सुधार पर चर्चा की

फोटो: हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

पेरिस

भारत के विदेशमंत्री डॉ. एस जयशंकर ने फ्रांस में हो रहे जी 7 विदेशमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने 'वैश्विक शासन में सुधार' विषयक सत्र को संबोधित किया। हालांकि भारत जी7 का सदस्य नहीं है। इस आयोजन के अध्यक्ष के नाते फ्रांस ने भारत को आमंत्रित किया है। फ्रांस के बुलावे जयशंकर कल रवाना हुए। यह बैठक राजधानी पेरिस के पास वॉक्स-डे-सेर्नें एबे में हो रही है। जयशंकर ने बैठक के कुछ फोटोज और अपनी सहभागिता के संबंध में एक्स पर पोस्ट किया, "जी 7 विदेश मंत्रियों की बैठक के सत्र में मैंने वैश्विक शासन में सुधार के विषय पर आमंत्रित साझेदारों के साथ चर्चा की। मैंने यूएनएससी में सुधारों, शांति स्थापना अभियानों को सुव्यवस्थित करने और मानवीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने की तात्कालिकता पर जोर दिया। विशेष रूप से, मैंने 'ग्लोबल साउथ' की ऊर्जा चुनौतियों, उर्वरक आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को उठाया।" उल्लेखनीय है कि फ्रांस पहुंचने पर जयशंकर का वहां के विदेशमंत्री जीन-नोएल बैरोट ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

पाकिस्तान के बलोचिस्तान में भूकंप, लोग घबराकर घरों से बाहर निकले

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत के झोब और उसके आसपास के इलाकों में गुरुवार रात आए भूकंप से दहशत फैल गई। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.2 दर्ज की गई। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए और कुरान की आयतें पढ़ने लगे। भूकंप के कारण झोब के किसी भी हिस्से से जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद स्थित राष्ट्रीय भूकंप निगरानी केंद्र ने कहा कि भूकंप का केंद्र झोब से 110 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में 12 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। स्थानीय प्रशासन और बचाव एजेंसियां स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं। इससे पहले गुरुवार की सुबह भी बलोचिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी केंद्र के अनुसार, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र बलूचिस्तान के बारखान से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर में था। इसकी गहराई जमीन से लगभग 92 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई।

अमेरिका छह अप्रैल तक नहीं करेगा ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला

एजेंसी (हि.स.)

वाशिंगटन/तेहरान

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी से छिड़े युद्ध पर अब राष्ट्रपति डोनाल्ड के स्वर कुछ धीमे पड़े हैं। उन्होंने अहम घोषणा की है कि अमेरिका 06 अप्रैल तक ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वह ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर हमले पर लगी रोक को एक हफ्ते से ज्यादा समय के लिए बढ़ा रहे हैं।

सीबीएस न्यूज और अल जजीरा चैनल की रिपोर्ट्स में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर घोषणा की कि अमेरिका ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों पर लगी रोक को 06 अप्रैल तक बढ़ाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि वह ईरानी सरकार के अनुरोध पर इस रोक को बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति ने इससे पहले सोमवार को ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले पर पांच दिन की रोक की घोषणा की थी। यह शनिवार को खत्म होने वाली है।

उन्होंने लिखा, ईरानी सरकार के अनुरोध के अनुसार, कृपया इस बयान को इस बात का प्रमाण मानें कि मैं ऊर्जा संयंत्रों को नष्ट करने की अवधि को 10 दिनों के लिए बढ़ाकर सोमवार, 06 अप्रैल, 2026 को रात 8 बजे (ईस्टर्न टाइम) तक कर रहा हूं। उन्होंने कहा, बातचीत जारी है और 'फेक न्यूज मीडिया' तथा अन्य लोगों के विपरीत दिए गए गलत बयानों के बावजूद, बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद! उन्होंने कहा: ईरान ने सात दिन मांगे थे। मैंने कहा, 'मैं 10 दिन दे रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे जहाज दिए। उनका इशारा उन कई तेल टैंकरों की ओर था, जिनके बारे में उनका कहना है कि ईरान ने सद्भावना दिखाते हुए उन्हें होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की इजाजत दी। इस बीच ईरान के एक नेता कहा कि तेहरान में अधिकारियों को अमेरिका का शांति प्रस्ताव मिला है। इस अधिकारी अधिकारी ने शांति प्रस्ताव को एकतरफा बताया है।

इस बीच, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पुष्टि की है कि इस्लामाबाद के युद्ध खत्म करने के लिए मध्यस्थता के प्रयास के तहत अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच संदेश भेज रहा है। इस प्रयास में तुर्किये और मिस्र भी सहयोग कर रहे हैं।

संक्षिप्त-समाचार

पश्चिम बंगाल: चुनाव आयोग ने बासंती हिंसा पर डीजीपी से मांगी रिपोर्ट

दक्षिण 24 परगना (पश्चिम बंगाल)। राज्य में चुनावी शोर के बीच दक्षिण 24 परगना के बासंती में पुलिस पर हमले की घटना में गुरुवार शाम तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। यह हिंसा । उस समय हुई जब भाजपा उम्मीदवार विकास सरदार इलाके में प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान कुछ हमलावरों ने लाठी-डंडों और बांस से अचानक हमला कर दिया। हालात काबू में करने पहुंची पुलिस टीम भी हमले का शिकार हो गई। हमले में सब-इंस्पेक्टर सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें दौड़ाकर पीटा गया और सड़क पर गिरने के बाद सिर पर वार किया गया, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके अलावा पांच अन्य कांस्टेबल भी जख्मी हुए हैं। स्थिति बिगड़ने पर कैनिंग, बासंती और गोसाबा कोस्टल थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। साथ ही एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे और बाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। इस पूरे घटनाक्रम पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए कई सवाल उठाए हैं। आयोग ने पूछा है कि केंद्रीय बलों की तैनाती में देरी क्यों हुई, केवल दो सेक्शन बल ही क्यों लगाए गए और इंटेलिजेंस इनपुट में चूक कैसे हुई। इन सभी बिंदुओं पर डीजीपी से जवाब मांगा गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तार सभी आरोपित तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के दौरान पुलिस पूरी तरह से आयोग के अधीन होती है, इसलिए किसी भी घटना की जिम्मेदारी आयोग की बनती है।

सर्राफा बाजार में सस्ता हुआ सोना, चांदी के भाव में मामूली गिरावट

नई दिल्ली। सिर्फ एक दिन की तेजी के बाद घरेलू सर्राफा बाजार में आज एक बार फिर गिरावट का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। शुरूआती कारोबार के दौरान सोना आज 1,970 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 2,140 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। दूसरी ओर, चांदी के भाव में आज 200 रुपये प्रति किलोग्राम की सांकेतिक कमजोरी दर्ज की गई है। कीमत में आई इस गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,44,540 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,44,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना आज 1,32,490 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,32,640 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में मामूली गिरावट आने के कारण ये चमकीली धातु आज दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,49,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर बिक रही है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,44,690 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,640 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,44,540 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,44,590 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,540 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,44,540 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,32,490 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है।

शुरूआती कारोबार में शेयर बाजार पर दबाव सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में आज अभी तक गिरावट का रुख है। कारोबार की शुरुआत भी कमजोरी के साथ हुई। बाजार खुलने के बाद बिकवाली का दबाव बना। इसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में गिरावट आ गई। हालांकि खरीदारों ने बीच-बीच में लिवाली का जोर बनाने की कोशिश भी की। इसकी वजह से इस सूचकांक की चाल में उतार-चढ़ाव होता हुआ नजर आया। पहले एक घंटे का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 1.41 प्रतिशत और निफ्टी 1.39 प्रतिशत की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। शुरूआती एक घंटे का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, टीसीएस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 1.66 प्रतिशत से लेकर 0.27 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर, श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर 5.80 प्रतिशत से लेकर 3.78 प्रतिशत तक की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 3,010 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इनमें से 697 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 2,313 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से चार शेयर लिवाली के सपोर्ट से हरे निशान में बने हुए थे। दूसरी ओर 26 शेयर बिकवाली के दबाव में लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

केंद्र ने पेट्रोल-डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर घटाया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच बीच आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर घटा दिया है। सरकार ने पेट्रोल पर इसको 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर अब 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीजल पर इसको 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य (0) कर दिया है। नई दरें शुक्रवार से लागू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय की आज जारी अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है जबकि डीजल पर यह शुल्क पहले के 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, सरकार के इस कदम से पेट्रोल- डीजल की कीमतें कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के लिए एक नया लेवी ढांचा पेश किया है। इन बदलाव के तहत, एटीएफ पर अब 50 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है, जिसकी आंशिक रूप से छूट के जरिए भरपाई की जाती है, जिससे विशिष्ट प्रावधान के तहत प्रभावी शुल्क लगभग 29.5 रुपये प्रति लीटर हो जाता है।

झारखंड के गढ़वा में महाष्टमी के जुलूस पर पथराव, 19 गिरफ्तार

थाना प्रभारी लाइन हाजिर

एजेंसी (हि.स.)

गढ़वा

झारखंड के गढ़वा जिले के रमकांडा थाना क्षेत्र में महाष्टमी को गुरुवार देररात निकाले गए जुलूस पर हुए पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। इस घटना में छह पुलिसकर्मी और अनेक नागरिक घायल हुए हैं। पुलिस ने 12 से अधिक मोटरसाइकिल जब्त की है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

पलामू डीआईजी कौशल किशोर और गढ़वा एसपी अमन कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एक समुदाय का आरोप है कि जुलूस को विशेष समुदाय के लोगों ने कौआखोह शिव चबूतरा के पास आगे जाने से रोक दिया। डीआईजी ने बताया कि रामनवमी की पूर्व संध्या पर पुलिस सुरक्षा में झांकी निकाली गई। इस दौरान जुलूस पर पथराव किया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गढ़वा एसपी अमन कुमार ने बताया कि जुलूस को लेकर दो समुदाय में विवाद हुआ था। जुलूस को लेकर बुधवार को भी थोड़ा विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों समुदायों में जुलूस निकालने पर सहमति बनी। मगर कुछ लोगों के अचानक जुलूस को रोकने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटनास्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने इस संबंध में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 13 लोग मुस्लिम पक्ष और 6 लोग हिंदू पक्ष के बताए जा रहे हैं। साथ ही 18 मोटरसाइकिलों और 9 मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अलग-अलग मामला दर्ज किया है। अन्य संदिग्धों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं: कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसका वास्तविक लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि भले ही सुर्खियों में कीमतें घटने की बात कही जा रही हो, लेकिन आम उपभोक्ताओं और डीलरों के लिए दरें लगभग जस की तस बनी हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार ने केवल ‖विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क‖ में कमी की है, जो तेल विपणन कंपनियां सरकार को अदा करती हैं। उनके अनुसार, इस कदम का सीधा फायदा जनता तक नहीं पहुंचा है। खेड़ा ने इसे एक अनावश्यक कर बताते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बाद से तेल विपणन कंपनियां घाटे का सामना कर रही थीं और सरकार ने अब जाकर उस बोझ का केवल एक छोटा हिस्सा कम किया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा दिखाई जा रही राहत केवल ‖कथानक‖ तक सीमित है, जबकि वास्तविकता में आम लोगों को कोई ठोस फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की कि सुर्खियां बनाने के बजाय उपभोक्ताओं को सीधे और वास्तविक राहत देने पर ध्यान दिया जाए।

ग्वालियर में सड़क हादसा, पांच लोगों की मौत, चार घायल

एजेंसी (हि.स.)

ग्वालियर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज तड़के थाटीपुर क्षेत्र स्थित परशुराम चौराहे पर जैन मंदिर के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की ऑटो रिक्शा से टक्कर हो गई। इस हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में जान गंवाने वालों में एक ही परिवार के कई सदस्य शामिल हैं। घायलों में दो बच्चे भी शामिल हैं, जिनका ग्वालियर के अस्पताल में इलाज चल रहा है।

यह हादसा तड़के करीब तीन बजे हुआ। ऑटो सवार लोग शीतला माता मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। ऑटो में कुल नौ लोग सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नीम के पेड़ से जा टकराया और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो चालक ने पहले बस स्टैंड के पास एक ई-रिक्शा को टक्कर मारी। इसके बाद पुलिस उसका पीछा कर रही थी। बचने के प्रयास में चालक तेज रफ्तार से वाहन भगाता हुआ आया और रास्ते में ऑटो को टक्कर मार दी। घायलों के मुताबिक, स्कॉर्पियो चालक नशे में था और लापरवाही से वाहन चला रहा था। स्कॉर्पियो में वो अकेला था। पुलिस ने आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

राजद सांसदों ने संसद भवन में किया प्रदर्शन बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसदों ने शुक्रवार को बिहार में आरक्षण का दायरा 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करने, वर्ष 2023 के जातीय सर्वेक्षण के आधार पर जनसंख्या अनुपात के अनुसार बढ़े हुए आरक्षण कोटे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने और एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर संसद भवन परिसर में मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया।

इस विरोध प्रदर्शन की अगुआई सांसद मीसा भारती ने की। उनके साथ सांसद संजय यादव, अभय कुशवाहा, अनिल कुमार यादव और अन्य राजद सांसद भी शामिल हुए। राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती हुई है, लेकिन इसके बावजूद देश में इन संसाधनों की उपलब्धता आसान नहीं है। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। राजद सांसद संजय यादव ने कहा कि 2022 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तब सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था। उसके आधार पर बिहार में जाति आधारित आरक्षण सीमा 75 प्रतिशत की गई, जिसमें 65 प्रतिशत दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए था। बिहार कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन लगभग तीन साल बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का रवैया दलित, ओबीसी और आदिवासी विरोधी है।

रिपोर्ट

रेमिटेंस और तेल की कीमतों में उछाल से गहराया संकट

युद्ध के कारण नेपाल के अर्थतंत्र पर संकट के बादल: एडीबी रिपोर्ट

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के एक अध्ययन में बताया गया है मध्यपूर्व के बढ़ते संघर्ष के कारण नेपाल जैसे रेमिटेंस पर निर्भर अर्थतंत्रों पर गंभीर असर पड़ सकता है। नवीनतम रिपोर्ट 'एडीबी ब्रिफ्स 384' के अनुसार, इस संघर्ष से ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाा में बाधा, वित्तीय स्थितियों में सख्ती और विशेष रूप से रेमिटेंस प्रवाह में बड़ी गिरावट का जोखिम बढ़ गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संघर्ष रेमिटेंस प्रवाह को सीधे प्रभावित करेगा, और नेपाल जैसे देशों पर इसका असर ज्यादा होगा जो पश्चिम एशिया से आने वाले रेमिटेंस पर अत्यधिक निर्भर हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 8.1 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशिया से आने वाले रेमिटेंस से आता है, जो एशियाई देशों में सबसे अधिक है। यदि पश्चिम एशियाई देशों की आर्थिक गतिविधियों में मंदी आती है, तो वहां काम कर रहे नेपाली श्रमिकों की मांग और आय घटेगी, जिससे नेपाल में आने वाली विदेशी मुद्रा पर सीधा असर पड़ेगा। ईंधन के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर नेपाल जैसे देशों के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि एक बड़ी चुनौती बन गई है। संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 120 डॉलर तक पहुंच गई थी।

यदि यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो एडीबी का अनुमान है कि एशिया के विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत अंक तक घट सकती है और मुद्रास्फीति 3.2 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। इसके प्रभाव से दक्षिण एशिया में महंगाई दर सबसे अधिक बढ़ने की संभावना है, जहां कीमतों में 4.9 प्रतिशत अंक तक वृद्धि हो सकती है। पश्चिम एशिया रासायनिक उर्वरकों का प्रमुख उत्पादन केंद्र भी है।

फोटो: हि.स.

संघर्ष के कारण कतर और सऊदी अरब जैसे देशों से यूरिया और अमोनिया के निर्यात में बाधा आई है, जिससे वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, 27 फरवरी की तुलना में 13 मार्च तक यूरिया की कीमत में 42.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे कृषि प्रधान देश नेपाल में खेती की लागत बढ़ेगी और खाद्यान्न कीमतों पर भी दबाव पड़ेगा। इसके अलावा, ओमान और हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख व्यापारिक मार्गों में बाधा के कारण ढुलाई (फ्रेट) दर और बीमा लागत में भारी वृद्धि हुई है। इसका सीधा असर नेपाल जैसे आयात-निर्भर देशों में सभी प्रकार के सामानों की कीमतों पर पड़ेगा।

इस संकट के प्रभाव को कम करने के लिए एडीबी ने सुझाव दिया है कि सरकारें ऊर्जा पर दी जाने वाली सब्सिडी को सभी के बजाय केवल अत्यंत गरीब परिवारों और प्रभावित उद्योगों तक सीमित करें। साथ ही, ऊर्जा की खपत कम करने और वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों को तेजी से अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। रेमिटेंस में संभावित गिरावट को देखते हुए विदेशी मुद्रा भंडार का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करने की भी सलाह दी गई है।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यह संकट एशियाई देशों की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों को फिर से उजागर करता है। यदि संघर्ष लंबा चलता है, तो नेपाल जैसे देशों की आर्थिक स्थिरता पर और भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

मियामी ओपन 2026: कोको गॉफ का शानदार प्रदर्शन, मुचोवा को हराकर फाइनल में पहुंचीं

एकतरफा मुकाबले में मुचोवा पस्त, 6-1, 6-1 से जीत दर्ज कर गॉफ ने रचा इतिहास

एजेंसी (हि.स.)
मैक्सिको सिटी

अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने दमदार खेल दिखाते हुए मियामी ओपन 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। गुरुवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में गॉफ ने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को एकतरफा अंदाज में 6-1, 6-1 से हराया। विश्व नंबर-4 गॉफ की शुरूआत भले ही धीमी रही और मुचोवा ने पहला गेम ब्रेक करते हुए बढ़त बनाई, लेकिन इसके बाद मुकाबले में गॉफ का पूरी तरह दबदबा देखने को मिला। उन्होंने तुरंत वापसी करते हुए स्कोर बराबर किया और फिर लगातार गेम जीतते हुए पहला सेट एकतरफा तरीके से अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में भी मुचोवा लय हासिल नहीं कर सकीं। उनसे कई अनफोर्स्ड एरर हुए, जिसका पूरा

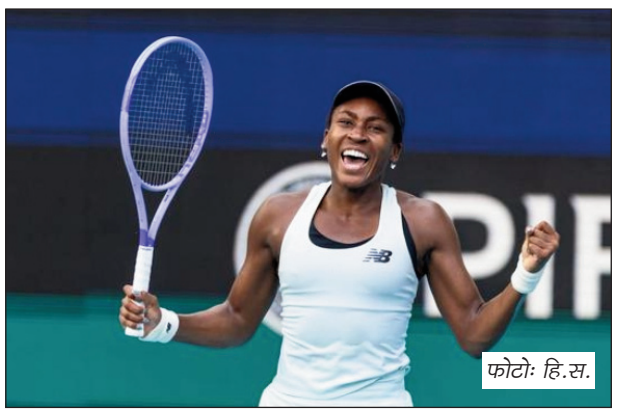
फोटोः हि.स.

फायदा उठाते हुए गॉफ ने तीन बार उनका सर्विस ब्रेक किया और मुकाबले को आसानी से जीत लिया। इस जीत के साथ गॉफ ने मुचोवा के खिलाफ अपना हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 6-0 कर लिया है।

मुचोवा इस मुकाबले से पहले शानदार फॉर्म में थीं। उन्होंने इस सीजन दोहा में खिताब जीता था और मियामी ओपन के क्वार्टरफाइनल में विक्टोरिया म्बोको को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची थीं, लेकिन गॉफ के सामने उनका प्रदर्शन फीका रहा। अब फाइनल में कोको गॉफ का मुकाबला वर्ल्ड नंबर-1 आर्यना सबालेंका से होगा, जहां दोनों खिलाड़ियों के बीच खिताब के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।

मियामी ओपन 2026: यानिक सिनर का दमदार प्रदर्शन, टियाफो को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे

मियामी। विश्व नंबर-2 इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने शानदार खेल दिखाते हुए मियामी ओपन 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने गुरुवार को खेले गए क्वार्टरफाइनल मुकाबले में मेजबान अमेरिका के फ्रांसेस टियाफो को एकतरफा अंदाज में 6-2, 6-2 से हराया। सिनर ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा और टियाफो को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने अपने सर्विस गेम में महज 9 अंक गंवाए और सिर्फ 71 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही सिनर ने मियामी ओपन में चौथी बार अंतिम चार में जगह बनाई है और मास्टर्स 1000 स्तर पर लगातार 30 सेट जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। मैच के बाद सिनर ने कहा कि शुरुआत में बढ़त लेना बेहद अहम होता है। उन्होंने कहा, जब आप मैच की शुरुआत में ब्रेक हासिल कर लेते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। मैं पूरे मैच में शांत रहने और मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता हूं, आज यही मेरी जीत की कुंजी रही। सिनर इस समय शानदार फॉर्म में हैं और ह्यासनशाइन डबलह्न (इंडियन वेल्स और मियामी ओपन दोनों खिताब जीतना) पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वे इंडियन वेल्स खिताब अपने नाम कर चुके हैं। अब सेमीफाइनल में सिनर का मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव या 18वीं वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरुंडोलो में से किसी एक से होगा।

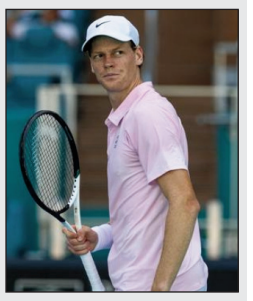

भारतीय कंपाउंड मिश्रित टीम ने स्वर्ण पदक जीता, व्यक्तिगत वर्ग में क्लीन स्वीप किया

एजेंसी (हि.स.)
बैंकॉक

भारत के कंपाउंड तीरंदाजों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शुक्रवार को यहां एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट के पहले चरण में मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक और महिला टीम का रजत पदक जीता और पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में क्लीन स्वीप किया। भारत ने इस तरह से अब इस प्रतियोगिता में दो स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक जीत दिए हैं। उसके कुल पदकों की संख्या आठ हो गई है जो पिछले साल के टूर्नामेंट के बराबर है। भारत ने दो कांस्य पदक बुधवार को महिला रिकर्व टीम और पुरुष कंपाउंड टीम ने जीते थे।

भारत को दिन में बाद में होने वाले अन्य फाइनल में महिला रिकर्व व्यक्तिगत (रिधि फोर) और पुरुष रिकर्व टीम से पदक मिलना सुनिश्चित है। दिन का मुख्य आकर्षण पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में क्लीन स्वीप रहा। उदय कंबोज ने रोमांचक फाइनल में हमवतन प्रथमेश जवकर को 145-144 से हराकर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता, जबकि अनुभवी खिलाड़ी रजत चौहान ने कांस्य पदक हासिल किया। चौहान ने अंतिम सेट में अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए तीन सटीक तीर लगाकर स्थानीय खिलाड़ी पीरावत रत्तनपोंगकियात को 145-144 से हराया जिससे भारत इस स्पर्धा में क्लीन स्वीप करने में सफल रहा। भारत के दो 22 वर्षीय खिलाड़ियों के बीच हुए मुकाबले में कंबोज ने अधिक अनुभवी प्रथमेश जवकर के खिलाफ कड़े मुकाबले में 145-144 से जीत हासिल की। इस मैच में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। जवकर दूसरे सेट के बाद 59-57 से आगे थे। कंबोज ने तीसरे सेट में 87-87 के स्कोर पर बराबरी करते हुए शानदार वापसी की और फिर चौथे सेट में जवकर की थोड़ी सी चूक का फायदा उठाते हुए 116-115 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने अंतिम सेट में अपना संयम बनाए रखा और यादगार जीत हासिल की। अठारह वर्षीय तेजल साल्वे ने तटस्थ ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा कर रही रूसी तीरंदाज मारिया दिमिडियुक को 144-135 से हराकर महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। तेजल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 तीरों में सिर्फ छह अंक गंवाए और एशिया कप में अपना दूसरा पदक हासिल किया। इससे पहले उन्होंने सिंगापुर में दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता था। सुबह के सत्र का मुख्य आकर्षण चिकिता तनिपार्थी और रजत चौहान की शीर्ष वरीयता प्राप्त मिश्रित टीम जोड़ी थी, जिन्होंने स्वर्ण पदक मुकाबले में दूसरी वरीयता प्राप्त मलेशिया को 158-156 से हराया।

विश्व कप से पहले स्पेन का आखिरी अभ्यास मैच पेरू से, मेक्सिको में होगा मुकाबला

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

स्पेन की फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप 2026 से पहले अपने अंतिम वॉर्म-अप मैच में पेरू का सामना करेगी। रॉयल स्पैनिश फुटबॉल फेडरेशन ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। यह मुकाबला 8 जून को मेक्सिको के शहर पुएब्ला में खेला जाएगा।

यह मैच यूरोपीय चैंपियन स्पेन के लिए विश्व कप अभियान शुरू होने से पहले आखिरी तैयारी का मौका होगा। स्पेन अपने पहले मैच में ग्रुप-एच में केप वर्डे के खिलाफ अटलांटा में उतरेगा। स्पेन इस महीने दो अन्य फ्रेंडली मैच भी खेलेगा, जिसमें सर्बिया और मिस्र के खिलाफ मुकाबले शामिल हैं। इससे पहले अर्जेंटीना के खिलाफ होने वाला फाइनलिसिमा मुकाबला कतर में प्रस्तावित था, लेकिन ईरान युद्ध के चलते इसे रद्द कर दिया गया। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी इस बार मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा मिलकर कर रहे हैं। टूर्नामेंट की शुरूआत 11 जून से होगी, जहां दुनिया की शीर्ष टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी।

आईपीएल 2026: 65 दिनों का क्रिकेट रोमांच आज से

एजेंसी (हि.स.)
बेंगलुरु

मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) शनिवार से यहां शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपना खिताब बचाने के लिए प्रतिबद्ध होगा जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर), चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और मुंबई इंडियंस अपनी खोई प्रतिष्ठा हासिल करने की कोशिश करेंगे। आईपीएल में अगले दो महीनों में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ कुछ युवा खिलाड़ियों पर भी नजर रहेगी जो अच्छा प्रदर्शन करके अपनी छाप छोड़ने में कोई कसर नहीं रखेंगे।

आरसीबी टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी करेगा और उसका लक्ष्य शानदार शुरूआत करना होगा। लेकिन इस मैच से पहले माहौल थोड़ा गंभीर बना हुआ है क्योंकि पिछले साल चार जून को आरसीबी के खिताब जीतने के जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और आरसीबी प्रबंधन ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति को बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। केएसएसीए ने स्टेडियम में 11 सीटें स्थायी रूप से खाली छोड़ने की घोषणा की है। इस स्टेडियम को आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए राज्य सरकार से अनुमति मिलने से पहले कई अनिश्चित महीनों का सामना करना पड़ा था। आरसीबी के खिलाड़ी पहले मैच के दिन अभ्यास सत्र के दौरान 11 नंबर की जर्सी पहनेंगे। जहां तक मैच का सवाल है तो आरसीबी और सनराइजर्स दोनों के पास गेंदबाजी संसाधनों की कमी है। आरसीबी को जोश हेजलवुड और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल के बिना खेलना होगा। दोनों ने 2025 के विजयी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से इस वर्ष वे अधिकतर मैचों में बाहर रहेंगे। हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया में चोट से उबरकर पूरी तरह फिट होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और वह बाद में टीम में शामिल हो सकते हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे दयाल पूरे सत्र से बाहर रहेंगे। आरसीबी को अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, स्पिनर क्रुणाल पंड्या, सुयश शर्मा और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मंगेश यादव पर काफी हद तक निर्भर रहना होगा। सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस भी शुरूआती चरण में टीम में नहीं होंगे। ईशान किशन को कार्यवाहक कप्तान बनाया गया है।

लेकिन सनराइजर्स के बैकअप विकल्प ज्यादा भरोसेमंद नहीं लगते। ब्रायडन कार्स, जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल और हर्ष दुबे को सपाट पिचों पर कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दोनों टीमें अपनी गेंदबाजी की कमजोरी का बल्लेबाजी से भरपाई करना चाहेंगी। आरसीबी के पास विराट कोहली, टिम डेविड, फिल साल्ट, जैकब बेथेल, कप्तान रजत पाटीदार, रोमारियो शेफर्ड जैसे बल्लेबाज हैं जबकि सनराइजर्स के पास भी ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, किशन और हेनरिक क्लासेन के रूप में धाकड़ बल्लेबाज हैं।

फीफा विश्व कप 2026 प्लेऑफः टोनाली चमके इटली ने नॉर्दर्न आयरलैंड को 2-0 से हराया

एजेंसी (हि.स.)
बर्गमो

फोटोः हि.स.

चार बार की विश्व चैंपियन इटली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप 2026 प्लेऑफ सेमीफाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ इटली अब 12 साल बाद विश्व कप में वापसी से सिर्फ एक कदम दूर है। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं, लेकिन दूसरे हाफ में इटली ने आक्रामक खेल दिखाया। 56वें मिनट में मिडफील्डर सैंड्रो टोनाली ने बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर टीम को बढ़त दिलाई। उन्होंने क्लियर किए गए क्रॉस पर तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए गेंद को एक बाउंस के बाद सीधे गोलपोस्ट के निचले कोने में पहुंचा दिया।

इसके बाद 80वें मिनट में फॉरवर्ड मोइज कीन ने टोनाली के पास पर शानदार मूव बनाते हुए डिफेंडर को छकाया और सटीक लो शॉट लगाकर मैच पूरी तरह इटली के पक्ष में कर दिया।

अब इटली का सामना फाइनल में वेल्स राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बोस्निया और हजेगोविना राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। यह मैच अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में जून-जुलाई में होने वाले विश्व कप 2026 में जगह बनाने के लिए निर्णायक साबित होगा।

धर्म दर्पण

कामदा एकादशी व्रत राक्षस योनि और घोर पापों से दिलाता है मुक्ति

हिंदू धर्म में एकादशी को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हर महीने दो एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इन दोनों एकादशियों का अपना-अपना विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस समय चैत्र मास चल रहा है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को बहुत ही विशेष माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तो आपके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा, जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं और सुख-समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं।

कामदा एकादशी तिथि

- कामदा एकादशी की तिथि आरंभः 28 मार्च, प्रातः 8 बजकर 45 मिनट से
- कामदा एकादशी की तिथि समाप्तः 29 मार्च,प्रातः 7 बजकर 46 मिनट तक
- व्रत हमेशा उदयातिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए 29 मार्च 2026 को ही कामदा एकादशी का व्रत रखना उचित है।

पूजा का शुभ मुहूर्त

- पूजा का शुभ समयः प्रातः 7:48 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक
- इस अवधि के दौरान विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है।

एकादशी व्रत पारण

- 30 मार्च , प्रातः 6:14 बजे से 7:09 बजे के बीच कामदा एकादशी का व्रत का पारण कर सकते हैं । इस समय व्रत का पारण (व्रत तोड़ना) करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है।

कामदा एकादशी व्रत का महत्व

कामदा एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने का भी एक माध्यम है। यदि इस दिन व्रत और पूजा-अर्चना पूर्ण विधि-विधान और श्रद्धा के साथ की जाए, तो जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इसलिए, इस पावन दिवस के महत्व को समझना और पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है।

कामदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा

प्राचीन काल में भोगिपुर नामक एक भव्य नगर था, जहाँ पुण्डरीक नाम का राजा राज्य करता था। उस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व निवास करते थे। उन्हीं में से एक गंधर्व जोड़ा था–ललित और ललिता। ललित और ललिता एक-दूसरे से अगाध प्रेम करते थे। ललित एक कुशल गायक था और ललिता एक अत्यंत सुंदर नृत्यांगना थी। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि वे एक-दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। एक दिन राजा पुण्डरीक की सभा में गायन का कार्यक्रम चल रहा था। ललित वहाँ मुख्य गायक के रूप में गा रहा था। गाते-गाते अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। ललिता के ध्यान में खो जाने के कारण ललित के गायन की लय बिगड़ गई और उसने अशुद्ध सुर लगा दिए। राजा के दरबार में उपस्थित 'कर्कोट' नामक नाग ने ललित की इस गलती को पकड़ लिया और राजा को बता दिया। राजा पुण्डरीक यह जानकर अत्यंत क्रोधित हो गए कि ललित ने मर्यादा का उल्लंघन किया और कर्तव्य के समय स्त्री का ध्यान किया। क्रोध में आकर राजा ने श्राप दियाः तूने मेरे सामने गाते समय अपनी स्त्री का स्मरण किया है, इसलिए तू 'कच्चा मांस' खाने वाला एक विशालकाय राक्षस बन जा। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक भयंकर राक्षस में बदल गया। उसका शरीर विशाल और डरावना हो गया, और वह वनों में भटकने लगा। अपने पति की यह दशा देखकर ललिता अत्यंत दुखी हुई। वह अपने पति को इस कष्ट से मुक्त कराने के लिए उसके पीछे-पीछे वनों में भटकती रही। भटकते हुए वह विन्ध्याचल पर्वत पर स्थित ऋषि श्रृंगी के आश्रम में पहुँची। ललिता ने ऋषि के चरणों में गिरकर अपने पति के उद्धार का मार्ग पूछा। ऋषि श्रृंगी ने दया भाव से कहा, ₹हे भद्रे! चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। तुम पूरी श्रद्धा के साथ इस एकादशी का व्रत करो और इसका पुण्य अपने पति को दान कर दो। इससे वह श्राप मुक्त हो जाएगा। ऋषि की आज्ञा मानकर ललिता ने विधि-विधान से कामदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष उसने प्रार्थना की, ₹प्रभु! मैंने जो भी व्रत और तप किया है, उसका फल मेरे पति को प्राप्त हो, ताकि वे राक्षस योनि से मुक्त हो सकें। व्रत के पुण्य प्रभाव से ललित तुरंत अपने राक्षस स्वरूप से मुक्त होकर पुनः एक सुंदर गंधर्व बन गया। स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई और दोनों विमान में बैठकर पुनः अपने नगर लौट आए। कामदा एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु की भक्ति और इस एकादशी के व्रत में इतनी शक्ति है कि यह घोर से घोर कष्टों और कुयोनियों से मुक्ति दिला सकती है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है।

धार्मिक महत्व

'कामदा' शब्द का अर्थ है 'कामनाओं को देने वाली'। पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में इस एकादशी के महत्व के बारे में निम्नलिखित बातें कही गई हैंः पापों से मुक्तिः मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य के जाने-अनजाने में किए गए जघन्य पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कष्टों का निवारणः यदि जीवन में निरंतर बाधाएं आ रही हों या मानसिक शांति का अभाव हो, तो यह व्रत सुख-समृद्धि के द्वार खोलता है।मोक्ष की प्राप्तिः यह व्रत न केवल भौतिक सुख देता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति में भी सहायक माना जाता है।

पूजा की संक्षिप्त विधि

कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 'वासुदेव' स्वरूप की पूजा की जाती है। इसकी सामान्य विधि इस प्रकार हैः संकल्पः प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। पूजनः भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं और पीले पुष्प, फल, धूप-दीप और नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी अर्पणः भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। मंत्र जापः 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। कथा श्रवणः शाम के समय कामदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें।

एयर शो में वायुसेना के विमानों के करतबों ने किया रोमांचित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ

केंद्रशासित चंडीगढ़ में सुखना लेक पर आज से दो दिवसीय एयर शो शुरू हो गया है। भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण टीम के आसमान में करबत देखकर दर्शक रोमांचित हो गए। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आसमान में तिरंगा बनाने के साथ ही डायमंड भी बनाया। इस वायुसेना की टीम में दो पायलट चंडीगढ़ के विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह और दिवाकर शर्मा भी शामिल थे।

नगर की सुखना लेक पर सुबह से ही एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। इस शो के लिए प्री बुकिंग की व्यवस्था की गई थी। इसलिए सुखना लेक को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। शो शुरू होने से पहले ही हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन न तो एयर शो पर कोई व्यवधान पड़ा और न ही दर्शकों के उत्साह में कोई कमी देखने को मिली। एयर शो शुरू होते ही नौ विमान आसमान में नजर आए। वायुसेना के बीएई हॉक एमके-132 विमानों ने करतब दिखाना शुरू किया।

एशिया की मानी हुई नौ विमानों की एरोबैटिक टीम के सदस्यों ने आसमान में डायमंड और अंग्रेजी का कैपिटल ए बनाकर दर्शकों हतप्रभ कर दिया। विमानों ने आसमान में तिरंगा बनाकर देशप्रेम का संदेश दिया। शो के दौरान प्रेसिजन फार्मेशन, लूप्स, रोल्स और डीएनए मूव भी दिखाए गए।

एयर शो के दौरान राज्य के मुख्य सचिव राजेश प्रसाद ने भारतीय वायु सेना की उत्कृष्टक्षमता, अनुशासन और समर्पण की सराहना की। उन्होंने इस भव्य आयोजन में योगदान देने वाले सभी विभागों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं को प्रेरित करने और देशभक्ति की भावना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस मौके पर चंडीगढ़ के डीसी निशांत कुमार, हरियाणा की फाइनेंसियल कमिश्नर रेवेन्यु सुनीता मिश्रा सहित तमाम अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

एयर शो के दौरान एनडीआरआफ के जवानों ने सुखना लेक में बोट के जरिए आसमान में पक्षियों पर नजर रखी। एयर शो को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। सुखना लेक 28 मार्च दोपहर तक आम लोगों के लिए बंद रहेगी और केवल पास धारकों को ही प्रवेश मिलेगा।

एयर शो का सिलसिला कल, 28 मार्च 2026 को भी जारी रहेगा। इस हवाई प्रदर्शन में पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने किए माता मनसा देवी के दर्शन, लिया आशीर्वाद

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर शुक्रवार को अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष के साथ पंचकूला स्थित ऐतिहासिक माता मनसा देवी मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मंदिर पहुंचने पर उपायुक्त एवं माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री सतपाल शर्मा ने राज्यपाल का स्वागत किया।

मुख्य मंदिर में दर्शन करने के उपरांत राज्यपाल ने मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला में मंत्रोच्चारण के बीच हवन-यज्ञ में भाग लिया और आहुति अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कंजक पूजन भी किया तथा कन्याओं को भोजन करवाया। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निशा यादव ने राज्यपाल को माता मनसा देवी का चित्र सम्मानस्वरूप भेंट किया।

इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज अत्यंत शुभ अवसर है, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता मनसा देवी मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए उमड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी धर्मपत्नी के साथ माँ मनसा के भक्त के रूप में मंदिर आए हैं और भारत व हरियाणा के लोगों के कल्याण तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना की है।

राज्यपाल ने आगे कहा कि उन्होंने माँ मनसा से एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए आशीर्वाद मांगा है, जो सशक्त, प्रगतिशील और करुणामय हो। उन्होंने कहा कि देश अपने नागरिकों, विशेषकर गरीबों और वंचित वर्गों के कल्याण के प्रति सदैव समर्पित रहे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत उदार मूल्यों को बनाए रखते हुए अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करता रहेगा तथा समावेशी विकास और सामाजिक सौहार्द सुनिश्चित करेगा।

इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त श्रीमती सृष्टि गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त एवं माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निशा यादव, श्राइन बोर्ड की सचिव श्रीमती शारदा प्रजापति, काली माता मंदिर के सचिव पृथ्वीराज सहित बोर्ड के सदस्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

पशुपालकों के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरूआत

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पशुपालकों के लिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से निःशुल्क परामर्श सेवा की शुरूआत की गई है। इस सेवा का उद्घाटन 27 मार्च, 2026 को श्री प्रदीप कुमार, सचिव, पशुपालन, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा किया गया। सेवा के शुभारंभ के अवसर पर सचिव, पशुपालन ने कहा कि पशुओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने में टेलीमेडिसिन की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार द्वारा इस सेवा को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। चंडीगढ़ में भी इस दिशा में प्रयास किए गए हैं और आज से यह सेवा पशुपालकों के लिए शुरू हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2021 को शुरूआत की गई थी, जिसका उद्देश्य एक एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करना है, जिससे पशु चिकित्सकों और पशुपालकों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जा सके तथा वास्तविक समय में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

श्री नवीन, निदेशक, पशुपालन ने बताया कि इस सुविधा के शुरू होने से पशुपालकों को उन परिस्थितियों में अपने पशुओं को पशु चिकित्सालय ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां उनकी शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होती, जैसे ऑपरेशन के बाद फॉलो-अप, सामान्य परामर्श, निगरानी तथा स्वास्थ्य कैलेंडर संबंधी मार्गदर्शन आदि। यह पहल पशुओं, उनके पालकों तथा पशु स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रामक जूनोटिक (पशुजनित) रोगों से सुरक्षित रखने तथा उनके प्रसार के जोखिम को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।

डॉ. अश्वनी कुमार, संयुक्त निदेशक, पशुपालन ने जानकारी देते हुए बताया कि यह टेलीमेडिसिन सेवा प्रतिदिन (रविवार को छोड़कर) दोपहर 2:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। पशुपालक टोल-फ्री नंबर 1800-180-2206 पर कॉल कर निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने चंडीगढ़ के पशुपालकों से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर श्री नवीन, निदेशक, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, डॉ. अश्वनी कुमार, संयुक्त निदेशक, डॉ. विशाल धवन, पशु चिकित्सा अधिकारी, डॉ. पी. के. सिंह, अनुसंधान अधिकारी, पशुपालन विभाग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

एसडी कॉलेज में आइडिया फोर्ज 26 का आगाज, छात्रों में दिखा स्टार्टअप का जोश

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज के इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी) की ओर से आयोजित एंट्रप्रेन्योरशिप इवेंट आइडिया फोर्ज ह्ल26 शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना और उन्हें उद्यमिता के प्रति प्रेरित करना है। यह कार्यक्रम तीसरी बार आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन कॉलेज के प्रिंसिपल और आईआईसी के अध्यक्ष डॉ. अजय शर्मा ने किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे उद्यमिता की सोच विकसित करें और समाज की समस्याओं के लिए नए और उपयोगी समाधान खोजें। आइडिया फोर्ज 26 छात्रों के लिए एक ऐसा मंच है, जहां वे उद्योग विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं, स्टार्टअप की दुनिया को समझ सकते हैं और उद्यमिता के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल सीख सकते हैं। इस कार्यक्रम में वर्कशॉप और इंटरएक्टिव सेशन आयोजित किए गए, जिनमें उद्यमिता की समझ, प्रोडक्ट-मार्केट फिट और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। इन सत्रों का संचालन इनोवेशन मिशन पंजाब में एसोसिएट आदिराज अहलूवालिया, इनोवेशन मिशन पंजाब में प्रोग्राम क्यूरेटर धवल काकू और कॉरपोरेट कानून व नियामक सलाह के क्षेत्र में चार दशक से अधिक अनुभव रखने वाले प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी आरपीएस खुराना ने किया। वर्कशॉप में 150 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने वक्ताओं से सवाल-जवाब और चर्चा में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, जिससे नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति के प्रति उनकी गहरी रुचि साफ दिखाई दी। इस कार्यक्रम का आयोजन आइडिया फोर्ज ह्ल26 के संयोजक डॉ. विक्रम सागर के मार्गदर्शन में किया गया। इसमें इनोवेशन एंबेसडर डॉ. आशीमा पाठक, डॉ. निधि मित्तल और डॉ. नीलू महाजन का सहयोग रहा। पहले दिन ने आगामी सत्रों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार किया। इस दौरान छात्रों को जरूरी जानकारी दी गई और उन्हें अपने विचारों को प्रभावशाली उद्यमों में बदलने के लिए प्रेरित किया गया।

संक्षिप्त-समाचार

आयुर्वेद के प्रति बढ़ रहा है विश्वास : डॉ. गौरव गर्ग

पंचकूला। माता मनसा देवी परिसर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकूला की ओर से आयोजित 9 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का शुक्रवार को समापन हुआ। स्वास्थ्य जांच शिविर में दो हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया। हर रोज 200 से 300 के बीच में श्रद्धालु अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने पहुंचे, जिन्हें निशुल्क दवाइयां वितरित की गई। खास बात यह भी रही कि मेले में ड्यूटी पर तैनात बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों और सेवादल के सदस्यों ने भी अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। शुक्रवार को संस्थान के डीन-इंचार्ज प्रोफेसर सतीश गंधर्व और उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. गौरव गर्ग ने शिविर का दौरा किया। उन्होंने शिविर में उपचार लेने पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जानीं और आयुर्वेदिक उपचार के प्रति जागरूक किया। शिविर में पहुंचने वाले लोगों ने भी आयुर्वेदिक उपचार से मिल रही राहत को सकारात्मक बताया। शुक्रवार को डॉ. अनूप एम, डॉ. आंकाक्षा राणा, डॉ. सुनीता यादव और डॉ. मानसी ग्रेवाल की टीम ने विभिन्न रोगों का परामर्श और उपचार प्रदान किया। इस अवसर पर डॉ. समित मसंद प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। डीन इंचार्ज प्रोफेसर सतीश गंधर्व ने कहा कि बदलते मौसम में आयुर्वेद अपनाना स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। आयुर्वेद में ऋतु परिवर्तन के अनुसार आहार और व्यवहार का विस्तृत वर्णन किया गया है, जो व्यक्ति को न केवल बीमारियों से बचाता है बल्कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। डीएमएस डॉ. गौरव गर्ग ने बताया कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में संस्थान के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) संजीव शर्मा और डीन प्रोफेसर गुलाब चंद पमनानी के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 से चैत्र और शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

मन संसार से नहीं केवल परमात्मा से जुड़ने पर ही स्थिर होता है: हरिमोहन गहलोत

चंडीगढ़। मन कोई 10-20 नहीं हर इन्सान में केवल एक ही मन होता है इन्सान चाहे तो इसे संसार में लगा ले या सत्गुरू के चरणों में लगा ले। संसार का स्वभाव परिवर्तनशील है इसमें हर पल बदलाव आते रहते हैं जिस कारण इन्सान का मन स्थिर नहीं होता लेकिन जो इन्सान अपने मन को सत्गुरू के चरणों में आकर परमात्मा की जानकारी प्राप्त करके इसके साथ जोड़ लेता है तो उसके मन में भी स्थिरता आ जाती है क्योंकि सारे ब्राहमण्ड में केवल ब्रहम ही सत्य है जिसमें आज तक कभी भी कोई बदलाव न तो हुआ है और न ही आगे हो सकता है इसलिए परमात्मा के साथ जुडने से इसे अपने मन में बसाने से मन में स्थिरता आ जाती है, दुनियां में और कोई साधन नहीं है जिससे हर परिस्थिति में इन्सान की एक ही मनोस्थिति हो। ये उद्गार आज यहां सैक्टर 30 में सन्त निरंकारी सत्संग भवन में हुए निरंकारी सत्संग में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रोताओं को सम्बोधित करते हुए जोधपुर राजस्थान के जोनल इन्चार्ज श्री हरिमोहन गहलोत जी ने व्यक्त किए। श्री गहलोत जी ने भक्त कबीर जी के एक दोहे का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार दीपक में जब तक तेल होता है तब तक वह जलता है ज्योंही तेल खत्म हो जाए तो दीपक बुझ जाता है और बुझ हुए दीपक को कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता इसी प्रकार इन्सान के अन्दर भी एक ही चेतना होती है जितनी देर तक यह चेतना शरीर में होती है इन्सान चल फिर रहा है, खा-पी रहा है बोल-सुन रहा है, सुख-देख का अनुभव कर पा रहा है लेकिन ज्यों ही चेतना शरीर से निकल जाती है तो शरीर के सभी अंग आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर आदि होते हुए भी ये काम करना बन्द कर देते हैं और घर के लोग भी फिर उस शरीर का ज्यादा समय तक घर में रखने के लिए तैयार नहीं होते, सगे-सम्बन्धी और धन दौलत सब यहीं रह जाता है इन्सान को अकेले ही जाना पड़ता है ।

पंचकूला के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने 'नींद से संबंधित श्वास विकारों' पर चर्चा के लिए किया महामंथन

पंचकूला। नागरिक अस्पताल, सेक्टर- 6 के कान, नाक और गला (ईएनटी) विभाग द्वारा आज रेड बिशप, सेक्टर 1 में ₹नींद से संबंधित श्वास विकार₹ (स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स) विषय पर एक सफल बहु-विषयक निरंतर चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डॉ. आर.एस. चौहान (आयोजन अध्यक्ष एवं पीएमओ) और डॉ. सुखदीप कौर (एचओडी ईएनटी आयोजन सचिव) के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। डॉ. मनीष बंसल, महानिदेशक स्वास्थ्य ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की जबकि डॉ. मुक्ता कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई । इसके अलावा सीएमई में संरक्षकः डॉ. आर.एस. चौहान, पीएमओ, डॉ संदीप बंसल , प्रोफेसर ईएनटी पीजीआई चंडीगढ़ स्लीप डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट सहित ईएनटी विशेषज्ञों, सर्जनों, एएसएमओ, एसएमओ और विभिन्न संकायों के रेजिडेंट डॉक्टरों सहित लगभग 100 डॉक्टरों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यह सीएमई अत्यंत सूचनात्मक और लाभकारी सिद्ध हुई, जिसमें नींद से संबंधित श्वास विकारों, विशेष रूप से ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए नवीनतम नैदानिक और प्रबंधन दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम के अंत में एक संवादात्मक पैनल चर्चा हुई, जिसके बाद वैलेडिक्टरी फंक्शन का आयोजन किया गया। इस आयोजन ने स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच बहु-विषयक सहयोग को बढ़ावा दिया और नैदानिक ज्ञान को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

यूआईईटी, पंजाब विश्वविद्यालय में डिग्री समारोह 2026 का आयोजन, 804 विद्यार्थियों को प्रदान की गई डिग्रियां

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (पंजाब विश्वविद्यालय) के 804 इंजीनियरिंग स्नातकों को पंजाब विश्वविद्यालय के सम्मेलन केंद्र में आयोजित डिग्री समारोह 2026 के दौरान डिग्रियाँ प्रदान की गईं। नव-संचालित इस सम्मेलन केंद्र में आयोजित इस प्रमुख शैक्षणिक समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. रेनू विग ने की, जबकि यूटी चंडीगढ़ के मुख्य सचिव श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। स्नातक विद्यार्थियों में कंप्यूटर विज्ञान अभियंत्रण के 185, सूचना प्रौद्योगिकी के 101, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियंत्रण के 190, यांत्रिक अभियंत्रण के 107, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण के 147 तथा जैव प्रौद्योगिकी के 74 विद्यार्थी शामिल रहे।

समारोह का एक प्रमुख आकर्षण विशिष्ट पूर्व छात्रों का सम्मान रहा, जिनमें नमन अग्रवाल, अखिल फिरानी, विक्रम सिंह बाजवा, प्रेरणा सिंह तथा धर्म पाल चौधरी सहित अन्य शामिल रहे। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों को पदक एवं शैक्षणिक सम्मान भी प्रदान किए गए। समारोह के अंत में वर्ष 2024 एवं 2025 के स्नातक बैच को औपचारिक रूप से डिग्रियाँ प्रदान की गईं तथा विशिष्ट पूर्व छात्र सम्मान भी प्रदान किए गए। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ, जिसमें डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन प्रो. योजना रावत, रजिस्ट्रार प्रो. वाई.पी. वर्मा, परीक्षा नियंत्रक प्रो. जगत भूषण तथा निदेशक यूआईईटी प्रो. सुखविंदर सिंह उपस्थित रहे। अपने प्रेरक संबोधन में श्री एच. राजेश प्रसाद (आईएएस) ने राष्ट्र निर्माण में अभियंताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए उन्हें श्रेष्ठतम बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को आजीवन सीखने की भावना अपनाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि जिस दिन सीखना रुक जाता है, उसी दिन विकास भी रुक जाता है। अपने संबोधन में कुलपति प्रो. रेनू विग ने वर्ष 2002 में स्थापना के बाद से यूआईईटी की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि चार विभागों से प्रारंभ होकर संस्थान आज छह स्नातक एवं अनेक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ लगभग 2,500 विद्यार्थियों का प्रमुख शैक्षणिक केंद्र बन चुका है। इस अवसर पर यूआईईटी के निदेशक प्रो. सुखविंदर सिंह तथा रजिस्ट्रार (प्रो. याजवेंद्र पाल वर्मा) ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों को बधाई दी और भविष्य में संस्थान के मूल्यों एवं उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। समारोह में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही, जो यूआईईटी एवं पंजाब विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि का प्रतीक रहा। कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से किया गया।

सात दिवसीय एनएसएस विशेष शिविर का भव्य समापन

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर-1, पंचकूला के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर का भव्य एवं गरिमामय समापन हुआ। समापन समारोह में महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. शैलजा छाबड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अपने संबोधन में डॉ. शैलजा छाबड़ा ने कहा कि एनएसएस केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त माध्यम है, जो उनमें सेवा, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है।

इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय एवं कीर्ति मलिक ने शिविर के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. अनिल कुमार पांडेय ने सात दिवसीय शिविर की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि शिविर के दौरान स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनजागरण, तथा विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों के माध्यम से स्वयंसेवकों ने न केवल समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान एवं नेतृत्व कौशल भी अर्जित किया।

आयोजन | कानून प्रवर्तन अधिकारियों से तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को पूर्णतः लागू करने का आह्वान

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कानून प्रवर्तन अधिकारियों का प्रशिक्षण चंडीगढ़ में संपन्न

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 से 25 मार्च 2026 तक चंडीगढ़ में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा पुलिस विभाग, यू.टी. चंडीगढ़ के सहयोग से पुलिस लाइन, सेक्टर-26, चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में चंडीगढ़ पुलिस के सब-इंस्पेक्टर एवं इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, यू.टी. चंडीगढ़ की निदेशक डॉ. सुमन सिंह ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा तथा तंबाकू से संबंधित रोगों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए तंबाकू नियंत्रण कानूनों के कड़े एवं निरंतर प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तंबाकू संबंधी उल्लंघनों को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सतत प्रवर्तन और जागरूकता ही तंबाकू उपयोग में कमी लाने की कुंजी है।

महत्वपूर्ण आंकड़े साझा करते हुए डॉ. राणा जे. सिंह ने बताया कि ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार चंडीगढ़ में तंबाकू उपयोग की दर लगभग 13.7% है, जो राष्ट्रीय औसत 28.6% से काफी कम है। हालांकि, उन्होंने यह भी चेताया कि बिना धुएं वाले तंबाकू का उपयोग बढ़ रहा है तथा कम उम्र में तंबाकू सेवन की शुरूआत चिंता का विषय बनी हुई है। ओपिंदर प्रीत कौर ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, शैक्षणिक संस्थानों के निकट तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा नाबालिगों को तंबाकू की उपलब्धता जैसे उल्लंघन शहरी क्षेत्रों में प्रमुख चुनौतियां बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की नियमित जांच और दंडात्मक कार्रवाई के माध्यम से इन कानूनों के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका है।

डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि तंबाकू सेवन विश्वभर में रोके जा सकने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है। उन्होंने ई-सिगरेट एवं वेप जैसे नए निकोटिन उत्पादों से उत्पन्न चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जिनके लिए सख्त निगरानी और प्रवर्तन आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. गोपाल चौहान ने सक्रिय प्रवर्तन दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विशेष रूप से सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि विशेषकर युवाओं में इसकी पहुंच को रोका जा सके। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर प्रभावी प्रवर्तन के व्यावहारिक सुझाव भी साझा किए।

तीन बैचों में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने और जन-जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों की व्यावहारिक दक्षता बढ़ाने के लिए इंटरैक्टिव रोल-प्ले सत्र भी आयोजित किए गए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चंडीगढ़ पुलिस के 150 से अधिक सब-इंस्पेक्टर एवं इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रतिभागियों ने नो टोबैको शपथ भी ली और तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के साथ-साथ अन्य लोगों को भी तंबाकू मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। उल्लेखनीय है कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं, विशेषकर धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध), के प्रवर्तन को चंडीगढ़ में मासिक अपराध समीक्षा का नियमित हिस्सा बनाया गया है।